धनबाद, गुरूवार
26 नवंबर 2026
वर्ष : 04 अंक : 55
पृष्ठ : 08
मूल्य: 3 /-
E-Mail:-truthpath941@gmail.com

हिन्दी दैनिक समाचार

ट्रूथ पथ



ब्रीफ न्यूज

जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में कलाकारों ने बिखेरी प्रतिभा

रामगढ़, (एजेंसी) :। झारखंड राज्य स्थापना दिवस-2026 पखवाड़ा के अवसर पर बुधवार को रामगढ़ जिले में जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड, रांची के निदेर्शानुसार जिला प्रशासन रामगढ़ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कलाकारों ने अपनी कला और सांस्कृतिक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन महर्षि ब्रह्मर्षि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोठार में किया गया।

प्रतियोगिता में गायन एवं नृत्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की आकर्षक झलक देखने को मिली। कलाकारों ने गजल, हिंदी गीत, नागपुरी गीत, भजन, सूफी गायन, झुमर, समूह नृत्य, लोक नृत्य, देशभक्ति गीत, लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य और जनजातीय संगीत की प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए लोक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और क्षेत्रीय पहचान को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।

मशीनों से कोयला लोडिंग के विरोध में मजदूरों ने किया प्रदर्शन

गोड्डा, (एजेंसी) :। ईसीएल की राजमहल परियोजना अंतर्गत मोंटे कार्लो की ओर से संचालित हुर्रा-सी ओपन कास्ट परियोजना में डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) के कोयला लोडिंग कार्य में मशीनों के इस्तेमाल को लेकर मजदूरों का आक्रोश सामने आया है। मजदूरों ने पारंपरिक रूप से हाथों से किए जाने वाले कोयला लोडिंग कार्य को मशीनों के माध्यम से कराए जाने का विरोध करते हुए इसे उनकी रोजी-रोटी पर हमला बताया है।

बुधवार को सैकड़ों की संख्या में मजदूर परियोजना के मुख्य गेट पर एकत्रित हुए और मशीनों के माध्यम से कोयला लोडिंग की व्यवस्था बंद कर पूर्व की तरह मजदूरों से काम कराने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना था कि वे लंबे समय से कोयला लोडिंग का कार्य कर दिहाड़ी मजदूरी प्राप्त करते थे। इसी से उनके परिवार का भरण-पोषण होता था। लेकिन अब कथित तौर पर स्थानीय स्तर पर मिलीभगत कर मजदूरों को काम से वंचित करते हुए मशीनों के जरिए कोयला लोडिंग कराई जा रही है।

एसआईआर से आदिवासी, दलित और मजदूर परेशान : चंद्रदेव

रांची, (एजेंसी) :। झारखंड विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा के दौरान माले विधायक चंद्रदेव महतो ने चुनाव आयोग से पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने की मांग की। उन्होंने विशेष सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई के दूसरी पाली में कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एसआईआर के तहत लाखों नागरिकों को नोटिस जारी किए जाने से विशेषकर आदिवासी, दलित और मजदूर वर्ग परेशान है।

चंद्रदेव महतो ने कहा कि मजदूरों को काम छोड़कर जरूरी दस्तावेज जुटाने और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं, विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों से हटाकर एसआईआर में लगाया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।उन्होंने कहा कि नाम, उम्र और पूर्वजों के नाम में मामूली अंतर जैसी विसंगतियों के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विस्थापन के कारण कई आदिवासी परिवारों के पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में पूर्वजों का नाम दस्तावेजों में नहीं होना मतदाता सूची से नाम हटाने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

होम्योपैथी के क्षेत्र में मजबूत अनुसंधान संस्कृति विकसित करने के लिए संस्थान मिलकर करें काम : राष्ट्रपति



भुवनेश्वर,(एजेंसी) : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुसंधान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और पेशेवर संगठनों से होम्योपैथी के क्षेत्र में मजबूत अनुसंधान संस्कृति विकसित करने के लिए आपसी सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी की भविष्य की विश्वसनीयता और अकादमिक प्रतिष्ठा काफी हद तक उसके अनुसंधान की वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा और उससे प्राप्त होने वाले नैदानिक साक्ष्यों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय होम्योपैथी वैज्ञानिक सम्मेलन में शिरकत करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी भारत की विविध स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुलभ, समतामूलक, वैज्ञानिक दृष्टि से जिम्मेदार और जनहित के प्रति संवेदनशील बनाने में संस्थानों, शोधकताओं, शिक्षकों तथा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका है।राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा से जुड़ा प्रत्येक निर्णय मरीज की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा का अंतिम उद्देश्य लोगों की पीड़ा को कम करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसलिए चिकित्सा के प्रत्येक क्षेत्र में मरीज का हित सर्वोपरि होना चाहिए।

उन्होंने होम्योपैथी के विकास में वैज्ञानिक अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण नैदानिक साक्ष्यों की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि होम्योपैथी की विश्वसनीयता और शैक्षणिक प्रतिष्ठा को मजबूत बनाने के लिए अनुसंधान में वैज्ञानिक ईमानदारी तथा प्रमाण आधारित दृष्टिकोण अनिवार्य है। उन्होंने अनुसंधान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और पेशेवर संगठनों से इस दिशा में मिलकर काम करने तथा अनुसंधान की मजबूत परंपरा विकसित करने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था का निर्माण आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

अमित शाह गुरुवार को संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम को करेंगे संबोधित



नई दिल्ली, (एजेंसी) :केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित ह्यसंविधान गौरव दिवसह्ण समारोह को संबोधित करेंगे। दिल्ली प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी। कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में आयोजित किया जाएगा।

दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह समारोह में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता होंगे। समारोह में दिल्ली के सांसदों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है।

कार्यक्रम में अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिकित्सकों, प्राध्यापकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की भागीदारी भी रहेगी। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना तथा संविधान निमार्ता डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान को याद करना है। यह आयोजन भाजपा के ह्यसंविधान गौरव अभियानह्ण के तहत किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। हालांकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन भारत गणराज्य बना। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। वर्ष 2026 में संविधान अंगीकार किए जाने के 77 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री पहुंचे लातेहार के मंगरा गांव, विधायक रामचंद्र सिंह के पुत्र विजय बहादुर सिंह के वैवाहिक कार्यक्रम में हुए शामिल



रांची(एजेंसी) : मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन अपनी धर्मपत्नी-सह-विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन के साथ आज लातेहार जिले के बरवाडीह स्थित मंगरा गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रामचन्द्र सिंह के सुपुत्र चि० विजय बहादुर सिंह के शुभ विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। इस मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन ने विजय बहादुर एवं आयु० कुमारी महिमा (नवदंपती वर-वधू) को स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके नवजीवन की सुखद शुरूआत की मंगलकामना की। साथ ही नवदंपती के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम, सद्भाव और खुशहाली सदैव बनी रहे, इसकी कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने विधायक तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों एवं सगे-संबंधियों से आत्मीय मुलाकात कर खुशी जाहिर की और परिवारजनों को भी इस मांगलिक कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं स्थानीय आम नागरिकों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को मंगरा गांव पहुंचने पर हैलिपैड पर स्थानीय प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर किया गया तथा स्वागत किया गया। मौके पर प्रमण्डलीय आयुक्त श्रीमती कुमूद सहाय, पलामू क्षेत्र के डीआईजी श्री किशोर कौशल, लातेहार उपायुक्त श्री संदीप कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री कुमार गौरव आदि पदाधिकारीगण, स्थानीय जन प्रतिनिधिगण एवं आम नागरिक उपस्थित रहे।

देहरादून आयुध निमार्णी में सीएम3 एमआर साइट का उत्पादन शुरू, पहली खेप में 21 साइट रवाना

फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ रणनीतिक साझेदारी से देश में उन्नत रक्षा तकनीकों के निर्माण को मिलेगा बढ़ावा, हजारों साइटों के उत्पादन का लक्ष्य



देहरादून, (एजेंसी) : रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) की देहरादून स्थित आयुध निमार्णी (ओएफडी) में सीएम3 एमआर साइट का उत्पादन शुरू हो गया है। बुधवार को आयोजित समारोह में पहली खेप के तहत 21 सीएम3 एमआर साइट रवाना की गईं।इस अवसर पर इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शर्मिष्ठा कौल शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक नए उत्पाद का निर्माण शुरू होने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के रक्षा औद्योगिक तंत्र में कंपनी की मजबूत पहचान स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने कहा कि फ्रांस की अंतरराष्ट्रीय कंपनी साफ्रान के साथ पिछले वर्ष हुआ समझौता अब इस महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचा है। पूर्व बोर्ड और नेतृत्व की दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 से ही सशस्त्र बलों को आधुनिक एवं उन्नत उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।शर्मा ने कहा कि आधुनिक रक्षा उत्पादन व्यवस्था में तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एलएंडटी और साफ्रान जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी इसी सोच का हिस्सा है। भविष्य में भी ऐसे तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि विशिष्ट रक्षा तकनीकों का निर्माण देश में ही किया जा सके और विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो।उन्होंने आयुध निमार्णी देहरादून के अधिकारियों, कर्मचारियों, यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधियों तथा उत्पादन से जुड़ी पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी उत्पाद की सफलता उसकी गुणवत्ता और समयबद्ध आपूर्ति से निर्धारित होती है। कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने, समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा निरंतर सीखने और सुधार की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि आयुध निमार्णी में नए भवन और उत्पादन प्रणालियों में किए जा रहे सुधार भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि देहरादून इकाई की टीम अपनी मेहनत और तकनीकी दक्षता के बल पर आने वाले समय में हजारों सीएम3 एमआर साइटों का उत्पादन करेगी। इससे देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और कर्मचारियों के लिए कार्य एवं कौशल विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे।

शर्मा ने बताया कि अक्टूबर के अंत में चंडीगढ़ से के9 वज्र कार्यक्रम के लिए जड़त्वीय नौवहन प्रणाली (इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम-आईएनएस) की पहली खेप रवाना की गई थी। इसी क्रम में अब देहरादून से सीएम3 एमआर साइटों की पहली खेप भेजी जा रही है। ये दोनों उपलब्धियां के9 वज्र परियोजना में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की बढ़ती भूमिका को दशार्ती हैं।

इस अवसर पर आयुध निमार्णी देहरादून के मुख्य महाप्रबंधक सी.एस. ठाकुर ने इसे इकाई के लिए गौरव का अवसर बताते हुए कहा कि पूरी टीम ने कड़ी मेहनत से इस उत्पाद को उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचाया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों

वाराणसी में 28 नवंबर से शुरू होगा काशी तमिल संगमम 5.0, तमिलनाडु से 1,400 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा



वाराणसी, (एजेंसी) :तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के काशी के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषायी और सभ्यतागत संबंधों को नई मजबूती देने वाला काशी तमिल संगमम का पांचवां संस्करण 28 नवंबर से वाराणसी में शुरू होगा। 12 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन की थीम ह्यतिरुक्कुरल पाईलवोमतिरुक्कुरल का अभ्यास करेंह्ण रखी गई है। इसके माध्यम से युवा पीढ़ी और देशभर के विद्यार्थियों को तमिल के महान शास्त्रीय ग्रंथ तिरुक्कुरल की नैतिक शिक्षाओं और जीवन मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

आयोजन में तमिलनाडु से करीब 1,400 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ये प्रतिनिधि वाराणसी के साथ प्रयागराज और अयोध्या का भी भ्रमण करेंगे। इस दौरान शैक्षणिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठियां, संवाद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आपसी समझ तथा सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ किया जाएगा।

काशी तमिल संगमम 5.0 के तहत देश के 1,000 उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर छात्र सहभागिता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक विषयों और भाषायी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के बीच तिरुक्कुरल की व्यापक समझ विकसित करना है। इसके तहत संरचित अध्ययन, शोध और परिसर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।प्रत्येक भागीदार संस्थान तिरुक्कुरल में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर मेरिट के आधार पर एक छात्र का चयन करेगा। चयनित विद्यार्थियों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और अंग्रेजी में ऑनलाइन शैक्षणिक अभिमुखीकरण दिया जाएगा। इसके बाद एक महीने तक शोध एवं शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। इसके लिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) की ओर से बहुभाषी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम की निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले प्रत्येक पात्र चयनित विद्यार्थी को 10 हजार रुपये की छात्रावृत्ति (स्टाइपेंड) भी दी जाएगी। विद्यार्थियों को संकाय मार्गदर्शक की देखरेख में चार से दस पृष्ठों का शोध लेख या शोध नोट तैयार करना होगा। साथ ही अपने संस्थान में तिरुक्कुरल विषय पर एक घंटे की प्रस्तुति भी देनी होगी।

काशी तमिल संगमम के दौरान तमिलनाडु के 50 शिक्षक उत्तर प्रदेश आएंगे। ये शिक्षक राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को तिरुक्कुरल की शिक्षाओं से परिचित कराएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु के विशेषज्ञ वाराणसी के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कक्षाएं और संवाद सत्र आयोजित करेंगे। विद्यार्थियों को ओरिएंटेशन मॉड्यूल, संवादात्मक सत्रों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से तिरुक्कुरल के नैतिक, सामाजिक और जीवनोपयोगी मूल्यों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य इस प्राचीन तमिल ग्रंथ की शिक्षाओं को युवाओं के दैनिक जीवन से जोड़ना है।कार्यक्रम के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के सहयोग से वाराणसी के स्कूलों में विशेष गतिविधियां आयोजित करेगा। इनमें पठन सत्र, कहानी सुनाने की गतिविधियां और रचनात्मक संवाद शामिल होंगे।

स्थापना दिवस पखवाड़ा: रोजगार, आवास, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में दिखी विकास की रफ्तार

रांची। झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा-2026 के तहत बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में विकास, जनकल्याण और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी व्यापक गतिविधियों का आयोजन किया गया। ह्यविरासत, प्रगति और आकांक्षाओं का उत्सवह्ण की भावना के साथ जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों ने ग्रामीण रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तीकरण, नशामुक्ति और वित्तीय समावेशन को केंद्र में रखकर कार्यक्रम आयोजित किए। पंचायतों से लेकर विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई।

आवास योजनाओं से साकार हुआ पक्के घर का सपना: पाकुड़ जिले के सभी छह प्रखंडों में 53 परिवारों ने गृह प्रवेश किया। सरायकेला-खरसावां में 61 परिवारों को नए आवास की सौगात मिली। सिमडेगा में 34 परिवारों तथा गोड्डा में 22 लाभुकों ने अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और पीएम-जनमन के तहत निर्मित घरों में प्रवेश किया। गढ़वा में भी विभिन्न पंचायतों में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण रोजगार और विकास को गति: सिमडेगा में विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत 8,408 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और 4,822 मानव दिवस सृजित करने की जानकारी दी गई। जिले की सभी 94 पंचायतों में विशेष ग्रामसभा आयोजित कर विकास योजनाओं के लिए 457 आवेदन प्राप्त किए गए।

शिक्षा और प्रतिभा को मिला मंच: लोहरदगा, गोड्डा, कोडरमा, दुमका, गढ़वा, चतरा सहित विभिन्न जिलों में क्विज, निबंध, पेंटिंग, नृत्य, गायन, नाटक और कथावाचन प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। विद्यार्थियों ने झारखंड की संस्कृति, इतिहास और विरासत से जुड़ी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

नशामुक्त समाज के लिए व्यापक अभियान: आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायतों में ठअढउऊफ के तहत जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, शपथ ग्रहण, पोस्टर, रंगोली और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। लोहरदगा में 128 विद्यार्थियों को बाल संरक्षण, बाल विवाह, बाल श्रम और नशामुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। रामगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 17,326 लोगों की सहभागिता दर्ज की गई।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: गोड्डा के बोआरीजोर में आठ गांवों में 222 बुखार पीड़ितों की मलेरिया जांच की गई, जिनमें 30 संक्रमित मिले। सरायकेला-खरसावां में खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। चतरा और अन्य जिलों में रक्तदान शिविरों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित किया गया। किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी: चतरा, दुमका, लोहरदगा और रामगढ़ में रबी फसल कार्यशाला, खेत बचाओ अभियान, बीज वितरण और आधुनिक कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया। किसानों को मृदा स्वास्थ्य, फसल संरक्षण और दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी गई।

महिला सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन: दुमका के सरैयाहाट में जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन हुआ। गोड्डा के मेहरमा में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट केंद्र शुरू किया गया। कोडरमा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मातृत्व, किशोरी स्वास्थ्य और महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई।

संक्षिप्त खबरें

शादी समारोह में चली गोली, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल



हजारीबाग के उपकार होटल में वारदात से मची अफरा-तफरी, सीसीटीवी फुटेज और शादी की रिकॉर्डिंग खंगाल रही पुलिस

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

हजारीबाग । हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र स्थित उपकार होटल में मंगलवार की रात शादी समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान अरनव सिंह के रूप में हुई है, जबकि गोली लगने से अंकित सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। आनन-फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया।

गोलीबारी की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस समारोह में मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और शादी समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही गोलीबारी के कारणों और अन्य पहलुओं पर कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा।

जेपीएससी-जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ भाजपा विधायकों का प्रदर्शन

विधानसभा के मुख्य द्वार पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी, लंबित नियुक्तियां जल्द पूरी करने की मांग

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची । झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले बुधवार को भाजपा विधायकों ने जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं तथा लंबित नियुक्तियों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा के मुख्य द्वार पर हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे भाजपा विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका कहना था कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से लेकर परिणाम जारी करने तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। नियुक्तियों में लगातार हो रही देरी के कारण लाखों अभ्यर्थी परेशान और निराश हैं।भाजपा विधायकों ने कहा कि राज्य के युवा लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा संबंधी विवादों और अनियमितताओं के कारण उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है।

विपक्ष ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं से जुड़े लंबित मामलों की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने और रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग की।

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी विपक्षी विधायकों का आक्रामक रुख जारी रहा। युवाओं के रोजगार और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का मुद्दा सदन में भी प्रमुखता से उठाया गया।

जन समाधान दिवस में उमड़े फरियादी, डीसी ने 15 दिनों में शिकायतों पर कार्रवाई का दिया निर्देश

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पलामू । पलामू समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जन समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रशासन के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

भूमि विवाद, अतिक्रमण, आवास योजना और पेयजल समेत कई समस्याएं उठीं, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए और 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जन समाधान दिवस के दौरान मुख्य रूप से भूमि विवाद, अवैध एलपीसी, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, दाखिल-खारिज, रास्ता अवरुद्ध करने और आवास योजना की किस्त से संबंधित शिकायतें सामने आईं।इसके अलावा सेविका चयन में कथित अनियमितता, पेयजल संकट, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन वितरण प्रणाली से जुड़ी समस्याओं को भी लोगों ने उपायुक्त के समक्ष उठाया।उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने तथा आवेदकों को की गई कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया।

विधायक रामचंद्र सिंह के पुत्र के विवाह समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

लातेहार । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन बुधवार को लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड अंतर्गत मंगरा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह के पैतृक आवास पर आयोजित उनके पुत्र अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह एवं महिमा कुमारी के विवाह समारोह में शिरकत की। समारोह स्थल पर पहुंचने पर विधायक रामचंद्र सिंह और उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री एवं कल्पना सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने नवदंपति से मुलाकात कर उन्हें सुखद, समृद्ध एवं खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने वर-वधू को नई जिंदगी की शुरूआत पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं।

25 से 30 साल से कार्यरत 119 ठेका कर्मियों के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट सख्त, तीन माह में फैसला देने का निर्देश

ट्रिब्यूनल को अंतिम अवॉर्ड सुनाने का आदेश, तब तक न नौकरी से हटाए जा सकेंगे कर्मचारी और न जारी होगा नया टेंडर

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची । धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआईएमएफआर) में करीब 25 से 30 वर्षों से अनुबंध पर काम कर रहे 119 कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद को तीन महीने के भीतर अंतिम फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने राजेश तिवारी समेत 14 तथा मनबोध कुमार मंडल सहित 105 याचिकाकताओं की याचिकाओं का निष्पादन करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल का अंतिम अवॉर्ड आने और उसकी सूचना पक्षकारों को मिलने के बाद चार सप्ताह तक संस्थान में मौजूदा व्यवस्था बरकरार रहेगी।

इस दौरान संस्थान प्रबंधन और संबंधित ठेका एजेंसी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं कर सकेंगे। साथ ही आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति के लिए कोई नया टेंडर भी जारी नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने यह अतिरिक्त समय इसलिए दिया है, ताकि ट्रिब्यूनल के फैसले से असंतुष्ट पक्ष को सक्षम न्यायालय में अपील करने का अवसर मिल सके।

दरअसल, राजेश तिवारी सहित



119 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 14 जुलाई 2023 को जारी टेंडर को चुनौती दी थी। याचिकाकताओं के अनुसार, वे वर्ष 1995 के आसपास से संस्थान में लगातार काम कर रहे हैं और उनके नियमितीकरण का मामला वर्ष 2006 से औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद में लंबित है।

कर्मचारियों का आरोप था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 के तहत न्यायाधिकरण की अनुमति लिए बिना नया टेंडर जारी किया गया। इसके माध्यम से उनकी सेवा शर्तों में बदलाव करने और उन्हें काम से हटाने की कोशिश की जा रही थी।

इससे पहले 21 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर कर्मचारियों को हटाने और नया टेंडर निकालने पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 12 अक्टूबर 2026 को न्यायाधिकरण ने हाईकोर्ट में दो रिट याचिकाएं लंबित होने का हवाला देते हुए अवॉर्ड पारित करने से परहेज किया था।

इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट याचिकाओं के लंबित रहने से न्यायाधिकरण को अपना फैसला सुनाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। उसे हाईकोर्ट की किसी प्रारंभिक टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं के आधार पर तीन महीने में निर्णय देना होगा।वहीं, संस्थान प्रबंधन की ओर से अंतरिम आदेश वापस लेने के लिए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई थी। प्रबंधन का तर्क था कि संबंधित कर्मचारी संस्थान के प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं, बल्कि ठेकेदार के अधीन कार्यरत हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि इन पहलुओं पर पहले ही विचार किया जा चुका है और करीब ढाई दशक से काम कर रहे कर्मचारियों को इस स्तर पर हटाना उचित नहीं होगा। अब सभी की निगाहें औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले पर टिकी हैं। तीन महीने के भीतर आने वाला निर्णय 119 कर्मचारियों के भविष्य और उनके नियमितीकरण की मांग के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।

हजारीबाग में ब्राउन शुगर तस्करी का भंडाफोड़, पांच आरोपी गिरफ्तार

23 पुड़िया में 11 ग्राम मादक पदार्थ बरामद, कार, दो बाइक और चार मोबाइल जब्त

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

हजारीबाग । हजारीबाग पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 23 पुड़िया में रखी करीब 11 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे एक चारपहिया वाहन, दो मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

पुलिस के अनुसार, बड़कागांव थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के कदमाड़ीह पुल के समीप कुछ युवक ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने पहुंचने वाले



हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अमन कुमार के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम गठित की गई।

पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर निगरानी शुरू की। इसी दौरान वहां कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर पांचों को पकड़ लिया।

इसके बाद सभी की तलाशी ली गई, जिसमें प्लास्टिक की 23 पुड़िया से करीब 11 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। मौके से अन्य सामान भी जब्त किया गया।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वे बड़कागांव थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचते थे। प्रत्येक पुड़िया की कीमत करीब एक हजार रुपये निर्धारित थी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अफताब आलम, मोहम्मद राजन अंसारी, मोहम्मद अल्ताफ हुसैन, रविंद्र कुमार महतो और पवन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी तेज करें, लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित हो : के. रवि कुमार

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची । झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारियां समय पर पूरी करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी अधिकारी जीरो पेंडेंसी के लक्ष्य के साथ काम करें और किसी भी स्तर पर आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बुधवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

बैठक में उन्होंने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों का अब तक निष्पादन नहीं हुआ है, उनकी व्यक्तिगत रूप से गहन जांच की जाए। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने, तथ्यों का सत्यापन करने और संबंधित मतदाताओं को सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाए।

के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान सुनवाई और दस्तावेजों के सत्यापन के साथ अन्य जरूरी कार्य भी निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। इसमें मतदान केंद्रों का नजरी नक्शा तैयार करना, मतदान केंद्रों की तस्वीरें लेना और जियो टैगिंग सहित अन्य तकनीकी जानकारियों को अपडेट करना शामिल है।

उन्होंने निर्देश दिया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों को उसी दिन ईसीआईनेट पोर्टल पर अपडेट किया जाए, ताकि किसी भी आवेदन के निष्पादन में अनावश्यक देरी न हो।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उन मतदान केंद्र क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जहां नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए अपेक्षाकृत कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सुपर चेकिंग के दौरान अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन की स्थिति की गहन समीक्षा करें।

उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन के दौरान अधिकारियों को लगातार कम से कम पांच घरों में जाना अनिवार्य होगा। वहां रहने वाले प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक के मतदाता सूची में शामिल होने की स्थिति की जांच की जाए, ताकि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित सभी जिलों के संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

एसआईआर पर लोगों को गुमराह कर रही राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग का सहयोग करे : बाबूलाल मरांडी

विधानसभा के विशेष सत्र में राजकीय संकल्प का किया विरोध, मतदाता सूची की शुद्धता को सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी बताया

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची । झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसाआईआर) को लेकर राज्य सरकार द्वारा लाए गए राजकीय संकल्प का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है और निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सरकार से एसआईआर में बाधा डालने के बजाय निर्वाचन आयोग को सहयोग करने की अपील की।मरांडी ने विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसके लिए मंत्रिपरिषद की बैठक तक नहीं की गई। कैबिनेट की स्वीकृति की प्रत्याशा में ही विधानसभा का सत्र बुला लिया गया।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा रहा एसआईआर पूरी तरह संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रिया है। मतदाता सूची के शुद्धीकरण में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न रहे। निर्वाचन आयोग के वैधानिक अधिकारों को राजनीतिक संकल्प के माध्यम से कमजोर करने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता।

नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा सदन में प्रस्तुत



आंकड़ों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार जिन मतदाता सूची के आंकड़ों का हवाला दे रही है, वह सूची अभी अंतिम रूप से प्रकाशित ही नहीं हुई है। प्रारूप सूची में नाम नहीं होना, नोटिस जारी होना और अंतिम रूप से नाम हटाया जाना तीन अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। सरकार इन सभी को एक साथ जोड़कर लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रही है।

मरांडी ने कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस शासनकाल में भी कई बार मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराया गया है। इसे नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया बताना पूरी तरह गलत है।

उन्होंने जमशेदपुर में अफगानी और राज्य में ईरानी नागरिकों के मिलने का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों की जांच निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से देश में रहने वाले लोग घुसपैठिये हैं, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ना के कारण भारत आने वाले हिंदू घुसपैठिये नहीं, बल्कि शरणार्थी हैं।

मरांडी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग किसी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बना रहा है। नागरिकों के दस्तावेज तैयार कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यदि लोगों को दस्तावेज बनवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो इसके लिए संबंधित सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि लोग परेशान हों, ताकि एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सके।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने प्रवासी मजदूरों और बेघर नागरिकों को ध्यान में रखते हुए भी अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह लोगों को जागरूक करे और अधिकारियों को पात्र मतदाताओं की सहायता करने का निर्देश दे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों का भी दायित्व है। आयोग ने बूथ लेवल एजेंट की व्यवस्था की है। ऐसे में राजनीतिक दलों को केवल आरोप-प्रत्यारोप करने के बजाय इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक टकराव से अधिक महत्वपूर्ण नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदान का अवसर मिले और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो। राज्य सरकार को एसआईआर में बाधा बनने के बजाय छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने में निर्वाचन आयोग का सहयोग करना चाहिए।

एचईसी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री करें हस्तक्षेप, विशेष पुनर्जीवन पैकेज देने की मांग : कैलाश यादव

एचईसी नागरिक परिषद ने जुताई बंद होने की आशंका, 29 नवंबर को धुर्वा में होगी अहम बैठक; आंदोलन की बनेगी रणनीति

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची । एचईसी की लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों के भविष्य पर मंडरा रहे संकट को लेकर एचईसी नागरिक परिषद के अध्यक्ष सह राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से एचईसी को बचाने के लिए विशेष पुनर्जीवन पैकेज (रिवाइवल पैकेज) देने और इसके पुनरुद्धार के लिए ठोस निर्णय लेने का आग्रह किया है।

कैलाश यादव ने कहा कि एचईसी देश का महत्वपूर्ण मदर इंडस्ट्रीज संस्थान है और एशिया के बड़े भारी उद्योग कारखानों में इसकी पहचान रही है। इसके बावजूद आज यह गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अपने लंबे कार्यकाल में एचईसी कई बार आर्थिक बदहाली का सामना कर चुका है और बीआईएफआर तक पहुंचा है। हालांकि, पूर्ववर्ती सरकारों ने विशेष आर्थिक पैकेज देकर इस महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान को बचाने की पहल की थी।

उन्होंने कहा कि एचईसी महज एक कारखाना नहीं, बल्कि देश की औद्योगिक विरासत है। रक्षा क्षेत्र, इसरो के चंद्रयान मिशन, पोखरण परमाणु परीक्षण और रेलवे सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए मशीनों का निर्माण कर संस्थान ने देश की तकनीकी क्षमता को मजबूती दी है।

यादव ने हालिया कानूनी घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए कहा कि चेन्नई की एक सप्लायर कंपनी द्वारा बकाया भुगतान को लेकर दायर याचिका के मामले में एनसीएलटी के आदेश से एचईसी के वित्तीय और संपत्ति संबंधी अधिकारों पर रोक लगने की स्थिति पैदा हुई है। इससे संस्थान के कर्मचारियों, अधिकारियों, विस्थापित परिवारों और एचईसी नगर परिसर में रहने वाले लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश के खिलाफ एचईसी के पास सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत मांगने का विकल्प है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार संस्थान को संकट से निकालने के लिए गंभीर पहल क्यों नहीं कर रही है। यादव ने आरोप लगाया कि करीब 32 महीने से कर्मचारियों और अधिकारियों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं एचईसी को धीरे-धीरे बंद कर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी तो नहीं की जा रही है।कैलाश यादव ने एचईसी नगर परिसर की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में बड़ी आबादी निवास करती है। यहां झारखंड सरकार का सचिवालय, न्यायालय और विधानसभा परिसर भी स्थित हैं। एचईसी क्षेत्र में लगभग 11 हजार आवास हैं, जबकि करीब 50 हजार झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवारों और व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका भी इस क्षेत्र से जुड़ी है।उन्होंने आवासों की लीज नवीकरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्ष 1995 से एचईसी के करीब 90 प्रतिशत आवास 90 वर्षों की दीर्घकालीन लीज पर दिए गए हैं। नियमानुसार प्रत्येक 30 वर्ष बाद इनका नवीकरण होना है। प्रथम नवीकरण की अवधि वर्ष 2025 में पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं होने से आवासधारकों में असमंजस बना हुआ है।

इन सभी मुद्दों को लेकर एचईसी नागरिक परिषद के बैनर तले आगामी 29 नवंबर को दोपहर ढाई बजे धुर्वा स्थित सीटीओ के पास न्यू मार्केट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी।

ट्रूथ पथ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक कुमार भारती के द्वारा डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, भास्कर प्रीटिंग प्रेस गोविंदपुर मेन रोड, अशोक नगर के.जी. आश्रम, धनबाद (झारखंड) से
मुद्रिक एवं नियर भाटिया शिव मंदिर, गांधी नगर धनबाद से प्रकाशित फोन नं. 7004605076, 9852421580
संपादक:- रवि रंजन * इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पी आर बी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उतरदायी। ई. मेल:-truthpath941@gmail.com आर. एन. आई.नंबर .-JHAHIN/2023/90593

संक्षिप्त खबरें

गोविंदपुर में राज्य स्थापना दिवस पर समारोह, लाभुकों के बीच 18 लाख रुपये वितरित



ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद । झारखंड राज्य स्थापना दिवस एवं राज्य सरकार के दूसरे वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर बुधवार को गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों एवं स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम में जेएसएलपीएस से जुड़ी तीन महिला स्वयं सहायता समूहों को छह-छह लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए। इस प्रकार तीनों समूहों के बीच कुल 18 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना एवं अंबेडकर आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए।

इसके अतिरिक्त 24 लाभुकों को साइकिल वितरित की गई। दिव्यांग लाभुकों को ट्राइसाइकिल और एक लाभुक को व्हीलचेयर प्रदान की गई। वहीं, तीन जरूरतमंदों को श्रवण यंत्र भी दिए गए।

कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिथिला देवी (छोटा जमुआ), रोहणी देवी (तिलैया), तनु देवी (आमटांड़), जगदीश रजक एवं वासु महतो (गोरगा) को निःशुल्क मसूर बीज वितरित किए गए।

इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जहीर आलम ने कहा कि गोविंदपुर प्रखंड प्रशासन सरकारी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की प्राथमिकता जरूरतमंद और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम में सीडीपीओ, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी उदित कुमार महतो, विधायक प्रतिनिधि, सहायक अभियंता अरुण कुमार सिंह, कृषि पदाधिकारी जसीम अख्तर, प्रधान सहायक अब्दुल मजीद सहित विभिन्न पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे।

पशुपालन एवं गव्य विकास योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण



ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद । झारखंड राज्य स्थापना पखवाड़ा समारोह के तहत बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से जिला पशुपालन एवं जिला गव्य विकास कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों एवं अनुदान राशि का वितरण किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों के चार लाभुकों को दुधारू गाय उपलब्ध कराई गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

योजना के तहत तीन महिला लाभुकों को दो गाय की इकाई पर 75 प्रतिशत अनुदान तथा एक पुरुष लाभुक को दस गाय की मिनी डेयरी इकाई पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया गया। दो गाय की इकाई की कुल लागत 1,35,050 रुपये निर्धारित है, जिसमें 1,01,288 रुपये सरकारी अनुदान और 33,762 रुपये लाभुक का अंशदान शामिल है। वहीं, दस गाय की मिनी डेयरी इकाई की लागत 6,75,250 रुपये है, जिसमें सरकार और लाभुक की ओर से 3,37,625-3,37,625 रुपये का अंशदान निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बकरी पालन, सूकर पालन, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन, कुक्कुट विकास एवं बत्तख-चूजा वितरण योजनाओं के लिए भी लाभुकों का चयन किया गया है। इन योजनाओं में पात्रता के आधार पर 90 प्रतिशत और 75 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।ब्रॉयलर कुक्कुट पालन योजना के तहत कलियासोल प्रखंड की उरमा पंचायत के दो लाभुकों अशफाक अंसारी एवं मोहम्मद रईस आलम का चयन किया गया। प्रत्येक लाभुक को 50,625 रुपये डीबीटी के माध्यम से तथा 16,744 रुपये के लाभुक अंशदान के आधार पर कुल 67,369 रुपये की इकाई का लाभ मिलेगा।बकरी विकास योजना के तहत धनबाद प्रखंड की पेटिया पंचायत के नकुल तुरी का चयन किया गया। उन्हें 44,640 रुपये की डीबीटी राशि और 4,747 रुपये के लाभुक अंशदान के साथ योजना का लाभ दिया जाएगा।वहीं, बकरी विकास योजना की ओएसपी 90 प्रतिशत श्रेणी के तहत बाघमारा एवं निरसा प्रखंड की चार महिला लाभुकों का चयन किया गया। इनमें बाघमारा प्रखंड के बांसजोड़ा की रूबी देवी एवं गंगा देवी तथा निरसा प्रखंड के बेनागोड़िया की आशा देवी एवं कमला देवी शामिल हैं। प्रत्येक लाभुक को 42,720 रुपये की डीबीटी राशि तथा 4,747 रुपये का अंशदान निर्धारित किया गया है।

बीसीसीएल सीएमडी ने ब्लॉक-दो की खदानों का किया निरीक्षण, उत्पादन बढ़ाने पर जोर

दैनिक लक्ष्य हासिल करने और कोयला डिस्पैच में तेजी लाने का निर्देश, सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष बल

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद । भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल ने बुधवार को ब्लॉक-दो क्षेत्र की विभिन्न खदानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खनन कार्यों, कोयला उत्पादन और डिस्पैच की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उत्पादन बढ़ाने और निर्धारित दैनिक लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के क्रम में सीएमडी ने विभागीय पैच के अलावा आउटसोर्सिंग कंपनियों अंबे माइनिंग और खेमका कैरियर के कार्यस्थलों का जायजा लिया। उन्होंने खदानों में कट की गहराई, पेनिट्रेशन दर, दो कट के बीच लगने वाले समय तथा प्रमुख मशीनों के संचालन और रखरखाव की स्थिति की जानकारी ली।

उन्होंने एमडीओ ऑपरेटरों और



संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता किए बिना खनन कार्यों को गति दी जाए। साथ ही प्लेटफॉर्म की अग्रिम तैयारी सहित सभी प्रारंभिक कार्य निर्धारित समय से पहले पूरे करने पर जोर दिया।

सीएमडी ने मार्च के शेष दिनों में उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायक मशीनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा न्यू मधुबन वाशरी को गुणवत्तायुक्त कोयले की आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया।

इसके बाद उन्होंने एबीओसीपी के विभागीय पैच, न्यू नदखुरकी हायर्ड पैच, न्यू बेनिडीह हायर्ड पैच और मोबाइल क्रशर साइट का निरीक्षण किया। यहां भी उत्पादन और डिस्पैच की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए तत्काल तेजी लाने को कहा।

पत्रकारों से बातचीत में सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह उनका नियमित निरीक्षण दौरा था। देश में बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए कोयला उत्पादन में वृद्धि जरूरी है। इसके लिए विभिन्न खदानों का निरीक्षण कर उनकी क्षमता और जरूरतों के अनुरूप विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से टीम भावना के साथ काम करने की अपील करते हुए उत्पादन के साथ सुरक्षा और कोयले की गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक कुमार रंजीव, एजीएम पीएसके सिन्हा, मैनेजर सुरेश प्रजापति, एरिया मैनेजर प्रताप चंद्र साहू, इंजीनियर इंचार्ज इंद्रानील मांझी, विद्युत एवं यांत्रिक प्रबंधक आलोक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

धनसार में बंद घर का ताला तोड़कर तीन लाख की चोरी, जेवरात और स्कूटी लेकर फरार हुए चोर



ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद । धनसार थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। मंगलवार देर रात हुई इस वारदात में चोर सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और स्कूटी लेकर फरार हो गए। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब तीन लाख रुपये आंकी गई है।

घटना के संबंध में पीड़ित शिवकुमार शर्मा ने धनसार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वह अपने निजी काम से घर से बाहर गए हुए थे। उस समय मकान में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ था।

इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी सहित अन्य सामान खंगाल डाले। चोरों ने सोने के मंगलसूत्र, बाली, नाक के आभूषण, चांदी की पायल समेत कई कीमती जेवरात चोरी कर लिए। इसके अलावा एलसीडी टीवी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, करीब 10 से 12 हजार रुपये नकद और घर में खड़ी स्कूटी भी लेकर फरार हो गए।

घर लौटने पर चोरी की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और लिखित शिकायत देकर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बेटी की विदाई पर भावुक हुए सांसद ढुलू महतो, छलके आंसू



ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद । राजनीति के मैदान में अपनी बेबाक और सख्त छवि के लिए पहचाने जाने वाले धनबाद के सांसद ढुलू महतो बेटी की विदाई के दौरान भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। बेटी को ससुराल विदा करते समय वे फूट-फूटकर रो पड़े। पिता और पुत्री के इस भावुक पल ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं।

विदाई की रस्मों के दौरान सांसद महतो अपनी बेटी से बिछड़ने का दर्द छिपा नहीं पाए। जिस बेटी को उन्होंने बचपन से उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसका हाथ किसी दूसरे परिवार को सौंपने की घड़ी उनके लिए बेहद भावुक कर देने वाली थी। घर-आंगन में उसकी हंसी और चहक से बनी रहने वाली रौनक के विदा होते ही माहौल गमगीन हो गया।

सांसद की आंखों में एक ओर बेटी के नए जीवन की शुरूआत की खुशी थी, तो दूसरी ओर उससे दूर होने का गहरा दुख साफ नजर आ रहा था। इस मार्मिक दृश्य के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग एक सख्त राजनीतिक नेता के भीतर छिपे संवेदनशील पिता की भावनाओं को देखकर भावुक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

धनबाद में आधुनिक रिकॉर्ड रूम का आईजी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने किया उद्घाटन

झारखंड में पहली बार धनबाद पुलिस को मिली आधुनिक रिकॉर्ड रूम की सुविधा, दस्तावेजों का रखरखाव होगा व्यवस्थित

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद । पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने बुधवार को धनबाद समाहरणालय परिसर में नवनिर्मित आधुनिक रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने फीता काटकर इस सुविधा का विधिवत शुभारंभ किया। इससे पहले जिला पुलिस बल की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

उद्घाटन समारोह में उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. याकूब मोहम्मद सहित कई



पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर आईजी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने कहा कि पुलिस विभाग में रिकॉर्ड रूम का विशेष महत्व है। विभिन्न मामलों की जांच, अनुसंधान और निष्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अलावा विभागीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने में इसकी अहम भूमिका होती है। आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनने से जरूरी दस्तावेजों का रखरखाव अधिक व्यवस्थित होगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उन्होंने इस पहल के लिए एसएसपी प्रभात कुमार के प्रयासों की सराहना की। आईजी ने बताया कि फिलहाल पूरे झारखंड में इस तरह की आधुनिक सुविधा धनबाद में उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में धनबाद पुलिसिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने के साथ पुलिस कार्यालयों में भी कई आधुनिक बदलाव देखने को मिलेंगे।

सूर्य सिंह बेसरा पर हमले के विरोध में धनबाद में धरना, हेमंत सरकार पर आंदोलनकारियों ने उठाए सवाल

निष्पक्ष न्यायिक जांच और पूर्व की तरह अंगरक्षक उपलब्ध कराने की मांग, मुख्यमंत्री की चुप्पी पर जताई नाराजगी

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद । झारखंड के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा पर कथित हमले के विरोध में आंदोलनकारियों ने बुधवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने और बेसरा को पूर्व की तरह अंगरक्षक उपलब्ध कराने की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।

धरने को संबोधित करते हुए झारखंड आंदोलनकारी दिलीप गोस्वामी ने कहा कि सूर्य सिंह बेसरा पर हुआ हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि यह झारखंड आंदोलन



की गरिमा और उसके संघर्षपूर्ण इतिहास से जुड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि बेसरा ने विनोद बिहारी महतो और गुरुजी शिबू सोरेन के साथ मिलकर अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पिता के पुराने सहयोगी और झारखंड आंदोलन के वरिष्ठ नेता की सुरक्षा एवं सम्मान को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए थी। इसके बावजूद सूर्य सिंह बेसरा को पहले की तरह अंगरक्षक उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है।

दिलीप गोस्वामी ने मुख्यमंत्री की ओर से घटना पर संवेदना तक व्यक्त नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने मांग की कि सूर्य सिंह बेसरा पर हुए हमले के पीछे की कथित साजिश का पदार्फाश करने के लिए निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए। साथ ही उन्हें तत्काल पूर्व की तरह सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेताओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मामले में गंभीरता दिखाते हुए शीघ्र उचित कदम उठाने की मांग की।

खुदिया नदी पुल के पिलर से फंदे पर लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, आधार कार्ड से हुई पहचान



ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद । गोविंदपुर-टुंडी मुख्य सड़क पर स्थित खुदिया नदी पुल के एक पिलर से बुधवार सुबह फंदे के सहारे लटका एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव पीले रंग की प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका हुआ था। रस्सी अपेक्षाकृत नई प्रतीत हो रही थी।

शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल गोविंदपुर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह कुछ लोग शौच के लिए नदी की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर खुदिया नदी पुल के पिलर से लटकते शव पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद रस्सी की मदद से शव को नीचे उतारा और तलाशी ली।

तलाशी के दौरान मृतक की जेब से एक आधार कार्ड बरामद हुआ। आधार कार्ड में नाम नरेश कुमार विश्वकर्मा, निवासी आनंद नगर, सरायढेला, धनबाद दर्ज है। हालांकि, आधार कार्ड में दर्ज नाम के आधार पर मृतक की आधिकारिक पहचान की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान सुनिश्चित करने और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।

लाभुकों को परिसंपत्ति, चेक और नियुक्ति पत्र वितरित, आठ महिला उद्यमियों को किया गया सम्मानित

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद। झारखंड राज्य स्थापना पखवाड़ा समारोह के तहत बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में जिला स्तरीय परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों, चेक, स्वीकृति पत्र एवं नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित करने तथा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। समारोह में उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने अनुकंपा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवनियुक्त कर्मियों तथा आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे।

इसके अलावा कृषि, भूमि संरक्षण, मत्स्य, उद्यान, पशुपालन विभाग एवं अग्रणी बैंक के माध्यम से संचालित योजनाओं के लाभुकों को स्वीकृति पत्र, परिसंपत्तियां और चेक प्रदान किए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं, क्विज, निबंध, गायन, कथा वाचन, वाद-विवाद एवं माइनिंग थीम पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बेहतर कार्य करने वाली महिला उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।समारोह में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने वाली धनबाद की आठ महिलाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने सरकारी सहायता का उपयोग कर अपने छोटे व्यवसाय एवं स्वरोजगार की शुरूआत की है।

इनके द्वारा संचालित व्यवसायों में कपड़ा दुकान, बताशा फैक्ट्री, पलाश दीदी कैफे, पलाश ऑयल मिल, ब्यूटी पार्लर, जूट बैग उत्पादन और हैचरी इकाई जैसे उद्यम शामिल हैं।

सम्मानित महिलाओं में निरसा प्रखंड के मदनडीह की मौसमी सिन्हा (कपड़ा दुकान), रूबी घोष (बताशा फैक्ट्री) एवं मीना रवानी (पलाश दीदी कैफे), टुंडी प्रखंड के कमारडीह की रानी दत्ता (राशन दुकान), गोविंदपुर प्रखंड के उदयपुर की गुड़िया कुमारी (ब्यूटी पार्लर), बाघमारा प्रखंड के राजगंज की नेहा देवी (जूट बैग उत्पादन), बलियापुर प्रखंड के प्रधानखंटा की बबीता कुमारी (हैचरी इकाई) तथा कलियासोल प्रखंड की शोभा गोड़ाई (सिलाई सेंटर) शामिल हैं।

धनबाद में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन, 50 से अधिक शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद । रणधीर वर्मा चौक स्थित सिटी सेंटर परिसर में जिला प्रशासन की ओर से चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में जिले के 50 से अधिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों द्वारा तैयार की गई आकर्षक एवं रचनात्मक कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया।

इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवा कलाकारों को अपनी रचनात्मक सोच, कलात्मक अभिव्यक्ति एवं प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना था। इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि नई पीढ़ी में असीम



रचनात्मक क्षमता मौजूद है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और सामने लाने के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाएं।उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और कलात्मक कौशल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।'लाइफ अराउंड माइंस' थीम पर आधारित इस अभियान के माध्यम से धनबाद की खनन संस्कृति, जनजीवन, ऐतिहासिक विरासत और स्थानीय परिवेश को चित्रों के जरिए जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों की कलाकृतियों के माध्यम से जिले की सांस्कृतिक पहचान और विशिष्टताओं को दर्शाया गया।जिला प्रशासन की यह पहल उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ धनबाद की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान को व्यापक स्तर पर सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

26-11-2026 T.P. Page 4_Layout 1 26-11-2026 07:13 Page 1

संक्षिप्त खबरें

कर्रा मेले में हथियार लहराकर लोगों से कर रहा था बदसलूकी, युवक गिरफ्तार

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

खूंटी । खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में आयोजित मेला समारोह के दौरान हथियार लहराकर लोगों को डराने और उनके साथ बदसलूकी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी रिवॉल्वर, गोली, मोबाइल फोन और लोहे का पंच बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि 24 नवंबर की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कर्रा थाना क्षेत्र में आयोजित मेले में एक युवक हथियार लहराकर लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीम गठित की गई और उसे घटनास्थल पर भेजा गया।

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी रिवॉल्वर, गोली, मोबाइल फोन और लोहे से बना पंच बरामद किया गया। लोहे के पंच का इस्तेमाल हाथ में पहनकर मुक्का मारने के लिए किया जाता है।

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अतीत के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह पहले नशे का आदी था और चार महीने तक नशा मुक्ति केंद्र में रह चुका है। हालांकि, पुलिस जांच में फिलहाल उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

सहायक अभियंता की प्रोन्नति पर तीन सप्ताह में निर्णय लेने का हाईकोर्ट का निर्देश

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची । झारखंड हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुनील कुमार राय की प्रोन्नति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए विभाग को तीन सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को कार्यपालक अभियंता के पद पर उनकी प्रोन्नति के मामले में समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है।

जमशेदपुर के मानगो निवासी सुनील कुमार राय ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर 22 मार्च 2024 से कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति देने तथा उससे जुड़े अन्य परिणामी लाभ प्रदान करने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति से पहले उनकी प्रोन्नति के मामले में निर्णय लिया जाना जरूरी है। उन्होंने यह भी दलील दी कि प्रार्थी को पहले से ही एसीपी/एमएसीपी के तहत कार्यपालक अभियंता का वेतनमान मिल रहा है। इसलिए उन्हें पदोन्नति देने से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब में प्रार्थी की पात्रता पर सवाल नहीं उठाया गया। सरकार ने अदालत को बताया कि सुनील कुमार राय सहित अन्य योग्य सहायक अभियंताओं की प्रोन्नति का मामला विभाग में विचाराधीन है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से सतर्कता स्वच्छता प्रतिवेदन और आंतरिक चरित्र रिपोर्ट मिलने के बाद प्रोन्नति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि सरकार ने याचिकाकर्ता की पात्रता को चुनौती नहीं दी है और उनका मामला पहले से प्रक्रियाधीन है। प्रार्थी की निकट भविष्य में होने वाली सेवानिवृत्ति को देखते हुए अदालत ने पथ निर्माण विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि 23 नवंबर 2026 के आदेश की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर उनकी प्रोन्नति पर विचार कर अंतिम और उचित निर्णय लिया जाए।

मेयर के पत्र और हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहे नगर आयुक्तः मुकेश अग्रवाल



ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची । झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्य एवं नगर निगम किरायेदार संघ के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने रांची नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त हाईकोर्ट के आदेशों और मेयर की ओर से भेजे जा रहे पत्रों को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसके कारण नगर निगम की दुकानों में कारोबार करने वाले दुकानदारों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।

मुकेश अग्रवाल ने बताया कि बाजारटांड़ स्थित नगर निगम की आवंटित दुकानों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दुकानदारों की समस्याओं के समाधान के लिए मेयर रोशनी खलखो ने भी नगर आयुक्त को कई पत्र लिखे हैं। इनमें दुकानों पर की जा रही कार्रवाई तत्काल रोकने और दुकानदारों की समस्याओं का उचित समाधान निकालने की मांग की गई है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि दुकानदार लंबे समय से पेनाल्टी, नामांतरण और नाम हस्तांतरण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वर्षों पुराने विवादों का समाधान किए बिना नगर निगम की ओर से लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और दुकानों को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। इससे कारोबारियों में असंतोष बढ़ रहा है। मुकेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी नगर निगम प्रशासन के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। उनकी मांग है कि दुकानदारों के साथ न्याय किया जाए और लंबे समय से लंबित मामलों का निष्पक्ष तरीके से निपटारा हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मेयर के पत्रों और हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद दुकानदारों को राहत नहीं मिली तो व्यापारी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

चौपारण सीएचसी के मुख्य द्वार पर अतिक्रमण और गंदगी से मरीज परेशान

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

हजारीबाग । हजारीबाग जिले के चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और गंदगी के कारण मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के गेट के आसपास ठेले, अस्थायी दुकानें और अव्यवस्थित वाहन पार्किंग से आवागमन बाधित हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉ. रजनीकांत कुमार ने अतिक्रमण हटाने के लिए अंचल अधिकारी (सीओ) को पत्र लिखा है।

चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि अस्पताल के मुख्य द्वार के आसपास दुकानों और ठेलों के कारण प्रवेश मार्ग बाधित हो रहा है। इसके अलावा लोग बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे अस्पताल का मुख्य गेट भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। नतीजतन बाहर से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल का प्रवेश द्वार खोजने में परेशानी होती है।

उन्होंने कहा कि गेट के आसपास गंदगी का अंबार लगा रहने से संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। मुख्य द्वार के समीप ही दाल-भात केंद्र संचालित है। ऐसे में खाद्य सामग्री तैयार करने और परोसने वाले स्थान के आसपास गंदगी रहना स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है।

एनसीएलटी की कार्रवाई से एचईसी पर संकट, बकाया वेतन को लेकर राज्यपाल से मिले मजदूर संघ के प्रतिनिधि

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी) की बिगड़ती स्थिति, एनसीएलटी की कार्रवाई और महीनों से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट झेल रहे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एचईसी मजदूर संघ ने राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया है।बुधवार को संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद और सचिव विकास तिवारी ने लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने एचईसी की मौजूदा स्थिति, एनसीएलटी द्वारा नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) अधिकारियों की कार्यशैली तथा उनके निर्णयों से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी दी।



महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने कहा कि एनसीएलटी के तहत नियुक्त आईआरपी अधिकारियों की कार्यप्रणाली के कारण संयंत्र के संचालन और कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। दूसरी ओर, लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण श्रमिकों के परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि परिवारों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है।

संघ के सचिव विकास तिवारी ने कहा कि देश के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एचईसी के श्रमिक आज आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर मजदूरों के हित और राष्ट्रीय औद्योगिक संपत्ति को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की कि कर्मचारियों के महीनों से लंबित वेतन का अविलंब भुगतान कराया जाए। साथ ही केंद्र और झारखंड सरकार संयुक्त रूप से हस्तक्षेप कर एचईसी को आवश्यक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराएं, ताकि संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से हो सके और संस्थान का अस्तित्व बचाया जा सके।

राज्यपाल ने मजदूर संघ की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाइयों और एचईसी की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए आश्वासन दिया कि इस मामले को राज्य एवं केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा।

मेदिनीनगर में महिला का शव फंदे से लटका मिला, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पलामू । पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में बुधवार सुबह एक 28 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। घटना बैरिया चौक स्थित बाजार समिति गेट के सामने एक मकान की है। मृतका की पहचान अमित कुमार की पत्नी दूजा कुमारी के रूप में हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है।

इधर, मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि दूजा कुमारी और उसके पति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद और अनबन चल रही थी। उसने आशंका जताई कि उसकी बहन की हत्या कर मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है।

मृतका के परिजनों ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

वहीं, पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, मायके पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों में नशामुक्ति अभियान, बच्चों और अभिभावकों ने ली जागरूकता की शपथ



ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

सरायकेला । झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत सरायकेला-खरसावां जिले में नशामुक्त समाज के निर्माण को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। समाज कल्याण विभाग की ओर से बुधवार को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया।

अभियान में बच्चों, किशोरों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों से जागरूकता रैली निकाली गई तथा लोगों को नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई।

जागरूकता अभियान को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला, रंगोली, गीत-संगीत, पोस्टर निर्माण और नारा लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान नशे की लत से प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता और सरकारी सेवाओं की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर जागरूकता रैलियां और सामुदायिक बैठकें आयोजित की गईं।

इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न संबंधित संस्थाओं ने सहयोग किया। समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को इस अभियान से जोड़ना है। विभाग ने सामूहिक भागीदारी के माध्यम से नशामुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश दिया।

झारखंड विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची । झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान सत्ता पक्ष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। वहीं, भाजपा ने विशेष सत्र को राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित बताते हुए सरकार के कदम का विरोध किया।



विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। इसे तत्काल रोककर नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की जरूरत है।

वित्त मंत्री ने दावा किया कि झारखंड में लगभग 2.21 करोड़ मतदाताओं में से करीब 27 प्रतिशत को संदिग्ध मानते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर किसी भी पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए।

प्रस्ताव में मांग की गई कि एसआईआर की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्रत्येक योग्य नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि सभी राज्यों और छोटे-बड़े राजनीतिक दलों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद पारदर्शी नियम तैयार किए जाएं। इसके बाद ही नए सिरे से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाए।

दूसरी ओर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार के रुख पर पलटवार किया। उन्होंने विशेष सत्र को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार एसआईआर के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है।

इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद झारखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं।

ऑपरेशन मुस्कान से खिले चेहरे, पुलिस ने 183 गुम मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची । झारखंड पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए। पुलिस की इस पहल से लंबे समय से अपने मोबाइल की तलाश कर रहे लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। तकनीकी संसाधनों, सीईआईआर पोर्टल और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने कुल 183 मोबाइल फोन बरामद किए।

अभियान के तहत विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारियों ने मोबाइल धारकों को उनके फोन सौंपे। मोबाइल लौटाने से पहले आवेदकों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, ताकि फोन सही व्यक्ति तक पहुंच सके।

रांची में भी बरामद हुए मोबाइल

राजधानी रांची में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिछले कुछ महीनों के दौरान चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए। लालपुर थाना क्षेत्र में दर्ज शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कई मोबाइल फोन खोज निकाले। इसके बाद संबंधित मोबाइल धारकों को थाने बुलाकर उनके फोन वापस सौंपे गए।



पलामू में 79 मोबाइल बरामद

पलामू जिले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों से 79 गुम मोबाइल फोन बरामद किए। बुधवार, 25 नवंबर को सत्यापन के बाद सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से मोबाइल खोने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली।

जामताड़ा में 12 मोबाइल लौटाए

जामताड़ा पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 12 गुम मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें नारायणपुर थाना क्षेत्र से दो, करमाटांड़ से तीन, मिहिजाम से दो, नाला से दो, बिंदापाथर, कुंडहित और बागडेहरी से एक-एक मोबाइल शामिल हैं। सभी मोबाइल सत्यापन के बाद उनके धारकों को सौंप दिए गए।

देवघर में 64 लोगों को मिली राहत

देवघर जिले में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 64 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस पाकर लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की।

लातेहार में 18 और बोकारो में 4 मोबाइल बरामद

लातेहार में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर साइबर सेल ने संचार साथी पोर्टल की सहायता से 18 गुम मोबाइल फोन बरामद किए। बुधवार को इन सभी मोबाइल को उनके वास्तविक धारकों को लौटा दिया गया।

वहीं, बोकारो में सिटी पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार मोबाइल फोन बरामद किए। ये सभी मोबाइल जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से गुम हुए थे। पुलिस ने सत्यापन के बाद उन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया।

होटवार जेल यौनाचार मामलाः पीड़ित को जान से मारने की धमकी, जेल के अंदर से फोन आने का आरोप

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची । होटवार जेल में एक बंदी के साथ कथित अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में अब पीड़ित और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप सामने आया है। पीड़ित के पिता का दावा है कि जेल के अंदर से फोन कर उनके बेटे को चुप रहने की चेतावनी दी गई है। फोन करने वाले ने धमकी दी कि यदि उसने मामले में मुंह खोला तो उसके पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

पीड़ित के पिता के अनुसार, 12 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज होने के अगले दिन यानी 13 नवंबर को उनके बेटे के मोबाइल पर फोन आया था। फोन करने वाले ने अपना नाम अरविंद बताते हुए कहा कि जेल के अंदर उसे चुप रहने की हिदायत दी गई थी, जिसे वह भूल गया है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा।

पीड़ित के पिता का आरोप है कि धमकी देने वाला व्यक्ति जेल के अंदर से ही फोन कर रहा था। उनका दावा है कि फोन करने वाला उन लोगों में शामिल है, जिन पर उनके बेटे ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार ने इस मामले को लेकर अपनी सुरक्षा पर भी चिंता जताई है।

पीड़ित के पिता ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सबसे पहले वे खेलगांव थाना पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया गया। आरोप है कि थाना प्रभारी ने उन्हें रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने रांची के एसएसपी से गुहार लगाई। एसएसपी के निर्देश के बाद खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इधर, पीड़ित ने दावा किया है कि होटवार जेल में वह अकेला बंदी नहीं है, जिसके साथ कथित तौर पर अप्राकृतिक यौनाचार हुआ है।

27 प्रतिशत आरक्षण और वैश्य आयोग के गठन की मांग, विधानसभा के समक्ष वैश्य मोर्चा का प्रदर्शन

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची । झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मांगों से संबंधित स्मार-पत्र सौंपा गया। स्मार-पत्र की एक प्रति लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी भेजी गई है।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु ने कहा कि संगठन पिछले 20 वर्षों से झारखंड में वैश्य समाज और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से मांगों पर अब तक अपेक्षित पहल नहीं की गई है।



उन्होंने राज्य में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने, वैश्य आयोग का गठन करने तथा छोटे दुकानदारों के 10 लाख रुपये तक के ऋण माफ करने की मांग उठाई। इसके अलावा वैश्य समाज के लोगों के साथ कथित शोषण, दमन, हत्या और लूट की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की भी मांग की।

महेश्वर साहु ने कहा कि राज्य की आबादी में वैश्य समाज की बड़ी हिस्सेदारी है। समाज की समस्याओं और अधिकारों पर गंभीर चर्चा के लिए उन्होंने राज्य की लगभग 52 प्रतिशत आबादी से जुड़े मुद्दों को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की।

प्रदर्शन में मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहु, वरीय उपाध्यक्ष रामसेवक प्रसाद, लक्ष्मण साहु, मुख्य प्रवक्ता रोहित कुमार साहु, संगठन महासचिव अनिल वैश्य, संगठन सचिव दिवाकर साहु, रांची जिलाध्यक्ष कृष्णदेव साहु, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कुमार साहु, आलोक कुमार साहु और केंद्रीय सदस्य मुकेश लाल सिंदूरिया सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए।

अयोध्या कैंट और जनकपुर धाम (नेपाल) के मध्य सरयू-कमला एक्सप्रेस का 28 नंवबर से किया जायेगा नियमित परिचालन

हाजीपुर, (एजेंसी) : अयोध्या कैंट और जनकपुर धाम (नेपाल) के मध्य गोरखपुर-नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-शीशो-जयनगर के रास्ते एक साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 15595/15596 का नियमित परिचालन दिनांक 28 नवंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि गाडी सं. 15595/15596 जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट-जनकपुर धाम एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का नियमित परिचालन जनकपुर धाम से 28 नवंबर से तथा अयोध्या कैंट से 30 नवंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। यह ट्रेन जनकपुर धाम से प्रत्येक शनिवार तथा अयोध्या कैंट से प्रत्येक सोमवार परिचालित की जायेगी। इस नई ट्रेन में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 03, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 03, शयनयान श्रेणी के 07 एवं एसएलआर के 02 कोच सहित कुल 17 कोच होंगे।

दिनांक 28 नवंबर से प्रत्येक शनिवार को गाड़ी सं. 15595 जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट सरयू-कमला एक्सप्रेस जनकपुर धाम (नेपाल) से नेपाली समयानुसार 13.10 बजे खुलकर नेपाली समयानुसार 14.25 बजे जबकि भारतीय समयानुसार 14.10 जयनगर कस्टम यार्ड पहुंचेगी तथा जयनगर कस्टम यार्ड से नेपाली समयानुसार 15.25 बजे जबकि भारतीय समयानुसार 15.10 बजे खुलकर 15.48 बजे मधुबनी,



17.10 बजे शीशो, 19.00 बजे सीतामढ़ी, 21.35 बजे रक्सौल, 22.50 बजे नरकटियागंज, अगले दिन 03.55 बजे गोरखपुर, 05.19 बजे बस्ती, 06.28 बजे मनकापुर, 07.25 बजे अयोध्या धाम रुकते हुए 08.10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। दिनांक 30 नवंबर से प्रत्येक सोमवार को गाड़ी सं. 15596 अयोध्या कैंट-जनकपुर धाम सरयू-कमला एक्सप्रेस अयोध्या कैंट से 17.50 बजे खुलकर 18.20 बजे अयोध्या धाम, 19.30 बजे मनकापुर, 20.37 बजे बस्ती, 22.13 बजे गोरखपुर, अगले दिन 01.50 बजे नरकटियागंज, 03.10 बजे रक्सौल, 04.42 बजे सीतामढ़ी, 06.05 बजे शीशो, 07.00 बजे मधुबनी रुकते हुए भारतीय समयानुसार 08.30 बजे तथा नेपाली समयानुसार 08.45 बजे जयनगर कस्टम यार्ड पहुंचेगी। जयनगर कस्टम यार्ड से यह भारतीय समयानुसार 10.30 बजे जबकि नेपाली समयानुसार 10.45 बजे खुलकर नेपाली समयानुसार 12.40 बजे जनकपुर धाम (नेपाल) पहुंचेगी।

संक्षिप्त खबरें

घने कोहरे में ट्रेनों की राह दिखाएगी एंटी फॉग डिवाइस

गया जी: सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। कोहरे के दौरान लोको पायलटों को सिग्नल और रेलवे ट्रैक से जुड़ी जानकारी समय से उपलब्ध कराने के लिए ट्रेनों में एंटी फॉग डिवाइस लगाई जा रही है। जीपीएस तकनीक से लैस यह एंटी फॉग डिवाइस घने कुहासे में लोको पायलटों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। इसके माध्यम से आगे आने वाले सिग्नल, रेलवे स्टेशन और रेलवे क्रॉसिंग की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। खास बात यह है कि संबंधित सिग्नल से करीब 500 मीटर पहले ही डिवाइस के डिस्प्ले पर अलर्ट दिखाई देने लगेगा। साथ ही आवाज के जरिए भी लोको पायलट को सतर्क किया जाएगा।

इससे कम दृश्यता की स्थिति में लोको पायलटों को सिग्नल की स्थिति समझने और ट्रेन की गति नियंत्रित करने में सहूलियत होगी। सर्दियों में घने कोहरे के कारण सिग्नल स्पष्ट नहीं दिखाई देने से रेल परिचालन प्रभावित होता है। कई बार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की गति कम करनी पड़ती है।

क्विज के सवालों में परखी गई लोकतंत्र की समझ, खुशी बनीं प्रखंड टॉपर



फतेहपुर (गया जी):लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी मजबूती जागरूक नागरिकों की समझ और भागीदारी पर निर्भर करती है। इसी सोच को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को टनकुप्पा प्रखंड सभागार में निर्वाचन साक्षरता क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने अपने ज्ञान, समझ और प्रतिभा का परिचय देते हुए निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सवालों के जवाब दिए। प्रतियोगिता में खुशी कुमारी ने सर्वाधिक अंक हासिल कर बाजी मार ली। निर्वाचन साक्षरता क्लब की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रखंड के चिह्नित विद्यालयों के 48 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों से मतदान का अधिकार, निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। निर्धारित समय में सवालों के जवाब देने के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखा। प्रतियोगिता का उद्देश्य किताबी ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की व्यावहारिक समझ देना भी था। प्रतियोगिता के परिणाम में खुशी कुमारी ने 50 में 44 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं दीपिका कुमारी और प्रवीण कुमार 43-43 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। रिशु कुमार और शान्वी राज ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। सफल प्रतिभागियों को बीडीओ गौरी कुमारी ने पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया।आयोजन में विद्यालयों के नोडल शिक्षक और संबंधित पदाधिकारी सक्रिय रहे। अधिकारियों ने कहा कि विद्यार्थियों को शुरूआती उम्र से ही मतदान के महत्व, मतदाता के अधिकार और चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी देना जरूरी है। इससे भविष्य में वे जिम्मेदार और जागरूक मतदाता बन सकेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चयनित विद्यार्थियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मौके पर बीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मैथिली को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने की घोषणा का मुकुंद चौधरी ने किया स्वागत



दरभंगा, (एजेंसी) : विद्यापति सेवा संस्थान के मिथिला विभूति पर्व समारोह के समापन अवसर पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी द्वारा मिथिला की भाषा, संस्कृति एवं शिक्षा के विकास को लेकर की गई घोषणाओं का जिला मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी ने स्वागत किया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैथिली को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने की घोषणा ऐतिहासिक पहल है।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में मैथिली शिक्षकों की नियुक्ति, मैथिली पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन तथा दरभंगा में नर्सरी से शोध स्तर तक संस्कृत की पढ़ाई के लिए गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करेगी। वहीं, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की पहल भी सराहनीय है।

मुकुंद चौधरी ने कहा कि मैथिली मिथिला की सभ्यता, संस्कृति और आत्मसम्मान की पहचान है, जबकि संस्कृत प्राचीन ज्ञान परंपरा की आधारशिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इन घोषणाओं को शीघ्र धरातल पर उतारकर मिथिला के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास को नई गति देगी। साथ ही उन्होंने सफल आयोजन के लिए विद्यापति सेवा संस्थान को साधुवाद दिया।

गझंडी स्टेशन की 120 वीं जयंती पर जुटेंगे रेल अधिकारी, 6 दिसंबर को भव्य समारोह

ऐतिहासिक ग्रैंड कॉर्ड रेल लाइन के उद्घाटन की याद में होगा आयोजन, रेलवे जीएम डिंपी गर्ग होंगी मुख्य अतिथि

गया जी(एजेंसी) : पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल अंतर्गत गया-कोडरमा रेल सेक्शन के ऐतिहासिक गझंडी रेलवे स्टेशन की 120वीं जयंती समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी 6 दिसंबर को स्टेशन परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के जीएम डिंपी गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जीएम के आगमन को लेकर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह है। स्टेशन परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। समारोह को यादगार बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं।गौरतलब है कि गझंडी स्टेशन का इतिहास भारतीय रेलवे





की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है। 6 दिसंबर 1906 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने गझंडी स्टेशन पर चांदी के स्पैनर से चांदी का बोल्ट कसकर ग्रैंड कॉर्ड रेल लाइन का उद्घाटन किया था। यह घटना भारतीय रेल के इतिहास में विशेष महत्व रखती है।इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रत्येक वर्ष स्टेशन की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार 120वीं जयंती समारोह को भव्य स्वरूप देने की तैयारी है। रेलवे जीएम की उपस्थिति से समारोह का महत्व और बढ़ने की उम्मीद है। ऐतिहासिक विरासत को याद करने के साथ रेलवे के गौरवशाली अतीत

डुमरीचट्टी में बहेगी अध्यात्म की बयार, मथुरा के आचार्य देंगे आत्मज्ञान का संदेश

27 और 28 नवंबर को देवी स्थान परिसर में होगा दो दिवसीय रामाश्रम सत्संग

फतेहपुर (गया जी): आत्मज्ञान की प्राप्ति और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार के उद्देश्य से फतेहपुर प्रखंड के डुमरीचट्टी बाजार में दो दिवसीय रामाश्रम सत्संग मथुरा का आयोजन किया जाएगा। 27 और 28 नवंबर को देवी स्थान परिसर में आयोजित होने वाले इस आध्यात्मिक समारोह में बड़ी संख्या में सत्संग प्रेमियों और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है।

सत्संग के दौरान मथुरा से आए आचार्य अपने प्रवचनों के माध्यम से मानव जीवन में आत्मज्ञान, ध्यान और साधना के महत्व पर प्रकाश डालेंगे।डुमरीचट्टी उपकेंद्र सत्संग परिवार के अर्जुन साव, राजेंद्र प्रसाद केशरी और सुरेश केशरी ने बताया कि सत्संग की प्रथम पाली 27 नवंबर को शाम सात बजे से रात नौ बजे तक तथा दूसरी पाली 28 नवंबर को सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक चलेगी। इसमें समर्थ गुरु परम संत डॉ. चतुर्भुज सहाय द्वारा प्रतिपादित आत्मज्ञान प्राप्ति की सरल एवं शीघ्र फलदायक साधना पद्धति की जानकारी उनके अनुभवों के आधार पर दी जाएगी। अनुभवी आचार्यों के सानिध्य में श्रद्धालुओं के लिए ध्यान, चिंतन और साधना का विशेष आयोजन भी होगा।आयोजकों ने बताया कि सत्संग सह भंडारा में सभी सत्संग प्रेमियों को सादर आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। सत्संग स्थल तक पहुंचने के लिए रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालु पहाड़पुर स्टेशन पर उतर सकते हैं, जबकि सड़क मार्ग से फतेहपुर होते हुए डुमरीचट्टी बाजार पहुंच सकते हैं।

कैबिनेट : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर

पटना,(एजेंसी) : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल में 11.884 डिसमिल बिहार सरकार की भूमि पर एसएसबी की 19वीं एवं 41वीं वाहिनी के वॉच टावर निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति सहित कुल 34 एजेंडों पर मपहर लगाई गई। इसके अलावे नालंदा के इस्लामपुर में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से मौजा-ब्रहगांवा में 564.37 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 382.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है।केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत पटना जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,794.32 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे शहर में स्वच्छ एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।ग्राम कचहरियों को और अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी के प्रशासनिक व्यय की वार्षिक राशि 4,000 से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2027 से 24,000 करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्राम कचहरियों के सुचारु संचालन और स्थानीय न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।समस्तीपुर में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए खानपुर अंचल के तीन मौजों में कुल 480 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 261.92 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी गई है।

सरकारी बस कर्मियों की हड़ताल से थमा परिचालन, यात्री बेहाल

गया जी(एजेंसी) : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के गया डिपो में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की हड़ताल से मंगलवार को सरकारी बसों का परिचालन प्रभावित रहा। बसों का परिचालन ठप रहने से आम यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस स्टैंड पहुंचे यात्रियों को दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ा। यात्री सुमित्रा कुमारी, हेमंत कुमार, कर्मवीर प्रसाद और रामलखन सिंह ने बताया कि सरकारी बसों का परिचालन बंद रहने से उन्हें काफी परेशानी हुई। यात्रियों का कहना था कि कर्मचारियों को समुचित सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि बसों का नियमित परिचालन जारी रहे और आम लोगों को परेशानी नहीं हो।इधर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा कर्मियों ने संघ के अध्यक्ष नवीन सिंह, प्रतिनिधि पंकज प्रसुनदास, राकेश शर्मा ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक राजकुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने मांगों पर विचार करने के लिए दो दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।

कर्मियों की प्रमुख मांग है कि प्राइवेट एजेंसियों के अधीन कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों को निगम के अधीन एक कंपनी में समायोजित किया जाए। इसके अलावा बिना समुचित आरोप के हटाए गए कर्मचारियों को वापस बहाल करने, मनमाने तरीके से ड्यूटी लगाने पर रोक, प्रत्येक महीने 20 दिनों की ड्यूटी सुनिश्चित करने तथा समय पर वेतन भुगतान और पे-स्लिप उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है। कर्मियों ने अधिकारियों के स्तर पर की जा रही मनमानी पर भी रोक लगाने की मांग की है। बताया गया कि गया डिपो से करीब 150 बसों का परिचालन होता है। इसके सफल संचालन के लिए लगभग 300 चालक, कंडक्टर और अन्य कर्मी कार्यरत हैं। वर्ष 2016 से बसों का परिचालन संविदा व्यवस्था के तहत कराया जा रहा है। वर्तमान में शिव कंपनी, ईएसईपीएल और मौर्य कंपनी के माध्यम से काम कराया जा रहा है। बिहार राजपथ परिवहन निगम गया डिपो के

प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि संविदा कर्मियों की मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। इसे विभागीय मुख्यालय को अवगत कराया जा रहा है। वहीं ईएसईपीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर मनजीत कुमार ने कहा कि सभी एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने की जरूरत है ताकि किसी भी कर्मी को परेशानी नहीं हो। इस दिशा में सभी एजेंसियां कदम उठा रही हैं।

वायरल ऑडियो ने गुरपा थानाध्यक्ष की कार्यशैली पर उठाए सवाल, आईजी से शिकायत

शराब तस्करी में बाइक जब्ती के बाद फोन पर हुई बहस की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल

थानाध्यक्ष पर गाली देने और फर्जी केस में फंसाने की धमकी का आरोप

शिकायतकर्ता ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का भी लगाया आरोप, डीएसपी बोले- ऑडियो और आवाज की कराई जा रही जांच

फतेहपुर (गया जी): गुरपा थाने की पुलिस कार्यशैली एक कथित वायरल ऑडियो को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही एक मिनट से अधिक की ऑडियो रिकॉर्डिंग में गुरपा थानाध्यक्ष शिवनंदन कुमार की कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकी भरी आवाज सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। मामले को लेकर हजारीबाग जिले के एक व्यक्ति ने मगध प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) से लिखित शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है। उधर, पुलिस ने वायरल ऑडियो और उसमें सुनाई दे रही आवाज की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, आज अखबार वायरल ऑडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।मामले की जड़ शराब तस्करी से जुड़े एक प्रकरण में बाइक जब्त किए जाने से जुड़ी बताई जा रही है। बताया जाता है कि गुरपा पुलिस ने शराब तस्करी के संदेह में एक बाइक जब्त की थी। इस दौरान बाइक सवार व्यक्ति पुलिस की पकड़ से निकल गया था। इसके बाद बाइक और संबंधित व्यक्ति को लेकर थानाध्यक्ष तथा दूसरे पक्ष के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसी बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि फोन पर थानाध्यक्ष ने गाली-गलौज की और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। बातचीत की रिकॉर्डिंग अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

अपहरण की सूचना देने पर मारपीट का भी आरोप :-हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के अंबातरी गांव निवासी देवनंदन यादव ने आईजी को दिए आवेदन में एक अन्य घटनाक्रम का भी जिक्र किया है। उनके अनुसार, 24 नवंबर को उनके ममेरे भाई वीरेंद्र कुमार को कुछ लोग तेतरिया जंगल के गम्हरिया गांव के पास से कथित रूप से अपहरण कर दुंदु की ओर ले जा रहे थे। इसकी सूचना उन्होंने गुरपा पुलिस को दी थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। बाद में थानाध्यक्ष ने फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो साक्ष्य उपलब्ध होने की बात भी कही है।शराब तस्करी के मामले दर्ज होने की पुलिस की जानकारी इधर, पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता देवनंदन यादव के खिलाफ विभिन्न थानों में शराब तस्करी समेत कई मामले दर्ज हैं। वहीं, शिकायतकर्ता ने इस आधार पर उनके आरोपों को खारिज करने के बजाय पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वजीरगंज डीएसपी अभिनव कुमार ने बताया कि वायरल ऑडियो की जांच कराई जा रही है। ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज की भी पड़ताल की जा रही है। जिला पुलिस मुख्यालय के निदेर्शानुसार जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्राथमिक शिक्षा में शामिल होगी मैथिली भाषा, एक सप्ताह में जारी होगी अधिसूचना : शिक्षा मंत्री

दरभंगा, (एजेंसी) : डॉ. नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह के तीसरे दिन मंगलवार की शाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, पर्यावरण मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद, सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. लक्ष्मीनिवास पांडेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा में मैथिली भाषा को शामिल करने संबंधी अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। मैथिली में पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन होगा तथा विद्यालयों में मैथिली शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही दरभंगा में गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी, जहां नर्सरी से शोध स्तर तक संस्कृत की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। उन्होंने मिथिला की भाषा, संस्कृति और परंपरा को देश की अमूल्य धरोहर बताया।पर्यावरण मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने अशोक पेपर मिल के संबंध में भी जल्द निर्णय लेने की बात कही। वहीं, राज्यसभा सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि महाकवि विद्यापति मिथिला की गौरवशाली पहचान हैं। उनकी स्मृति में 54 वर्षों से समारोह का आयोजन किया जाना सराहनीय सांस्कृतिक पहल है।इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सहित वरिष्ठ अधिवक्ता शंभुनाथ झा, प्रो. दिनेश झा, केशव कुमार चौधरी, डॉ. संजीव कुमार चौधरी एवं लोक गायिका जूली झा को मिथिला विभूति सम्मान प्रदान किया गया।अतिथियों का स्वागत विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉ. बैद्यनाथ चौधरी 'बैजू' ने किया। कार्यक्रम का संचालन पं. कमलाकांत झा ने किया।

संपादकीय

धर्म और सत्ता की सियासतः सनातन संस्कृति के सामने बढ़ती चुनौतियां

धर्म आस्था, विश्वास, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का आधार है। इसका उद्देश्य समाज को जोड़ना, सद्भाव बढ़ाना और व्यक्ति को सत्य, सेवा तथा परोपकार के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना है। लेकिन जब धर्म का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने, चुनावी लाभ उठाने और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए होने लगता है, तब उसका प्रभाव केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत पर भी पड़ता है। भारत में पिछले तीन दशकों के दौरान धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने इसी तरह के सवाल खड़े किए हैं।

आजादी के बाद संविधान लागू होने से लेकर वर्ष 1990 तक भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने की कोशिश होती रही। हालांकि उस दौर में भी धार्मिक और सामुदायिक विवाद सामने आते थे, लेकिन 1990 के बाद धर्म को चुनावी राजनीति का प्रभावशाली माध्यम बनाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी। इसके साथ ही धार्मिक आस्था और राजनीतिक विचारधारा के बीच की दूरी कम होती चली गई। धर्म के नाम पर राजनीतिक लामबंदी होने लगी और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल चुनावी रणनीति का हिस्सा बनता गया।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि धर्म की रक्षा और प्रचार का दावा करने वाले कुछ चर्चित धार्मिक चेहरों के आचरण और बयानों को लेकर भी समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। रामदेव, आसाराम, राम रहीम और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जैसे अलग-अलग पहचान वाले चर्चित व्यक्तित्वों से जुड़े विवादों ने धार्मिक नेतृत्व की भूमिका पर बहस को जन्म दिया है। कुछ मामलों में कानूनी आरोप और न्यायिक कार्यवाही हुई है, तो कुछ में बयानों तथा धार्मिक गतिविधियों को लेकर सवाल उठे हैं। इन घटनाओं ने श्रद्धालुओं के सामने यह विचार करने का अवसर पैदा किया है कि धर्म के नाम पर स्थापित होने वाली व्यवस्थाओं की वास्तविक प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हाल के दिनों में बाबा रामदेव और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच सामने आए वैचारिक मतभेदों तथा सार्वजनिक बयानों ने इस चर्चा को और व्यापक बना दिया है। सवाल यह है कि धार्मिक मंचों पर एक-दूसरे को चुनौती देने, किसी को पाखंडी बताने अथवा भगवान राम और कृष्ण के नाम का सहारा लेकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश से सनातन धर्म को क्या हासिल होगा?

भाजपा को सत्ता से हटाने चले, सीटों पर ही उलझे विपक्षी दल

2027 की लड़ाई से पहले विपक्ष दिल्ली की बैठकों में उलझा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा को हराने का दावा करती हैं, पर उनकी बातचीत का केंद्र जनता, बेरोजगारी या महंगाई नहीं, सीटों की गिनती और राजनीतिक हैसियत बन गई है। जिस गठबंधन को भाजपा के लिए चुनौती बनना था, वह अभी अपने भीतर भरोसा कायम नहीं कर पा रहा। यह कमजोरी भाजपा के लिए अवसर है। सपा ने कांग्रेस के सामने 26 सीटों का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस की ओर से पहले 181 सीटों की मांग की खबर आई, फिर 130 और 120 सीटों के आसपास की दावेदारी सामने आई। फासला साफ है। अखिलेश का तर्क है कि सीटें जीतने की संभावना के आधार पर मिलनी चाहिए। पर जीत का पैमाना कौन तय करेगा? क्या सपा अपने उम्मीदवारों को भी इसी कसौटी पर परखेगी? कांग्रेस की हालत भी किसी भ्रम में रहने लायक नहीं। 2022 में उसने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ दो जीतीं, उसका वोट प्रतिशत 2.33 रहा और 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। ऐसे प्रदर्शन के बाद 120-130 सीटों का दावा आत्ममुग्धता लगता है। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की 17 में से छह सीटें जीतीं और 9.46 प्रतिशत वोट पाए। सपा ने 62 में से 37 सीटें जीतकर 33.60 प्रतिशत मत हासिल किए। लोकसभा नतीजे विधानसभा की गारंटी नहीं, लेकिन कांग्रेस शून्य भी नहीं। दोनों दल अपने अनुकूल आंकड़े चुन रहे हैं। सपा की 26 सीटों वाली सूची में रामपुर खास और फरेंदा जैसी कांग्रेस की जीती सीटें हैं। मथुरा, खेरागढ़, जगदीशपुर और किदवई नगर वे क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। बागपत, मोदीनगर, हापुड़, जेवर, स्याना, खुर्जा, खैर, इगलास, मांट, आगरा उत्तर, फतेहपुर सीकरी, बिलग्राम-मल्लावां, गोविंद नगर, नानपारा, गोरखपुर शहर, खजनी, पडरौना, फाजिलनगर, पिंडरा और वाराणसी कैंट भी प्रस्ताव में बताए गए हैं। कई क्षेत्रों में कांग्रेस के हजार-दो हजार वोट सपा के तर्क को बल देते हैं, पर जीत उम्मीदवार, समीकरण, संगठन और वोट हस्तांतरण से तय होगी।

अखिलेश की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यह हो सकती है कि वह गठबंधन को साझेदारी नहीं, अधीनता समझ बैठें। पांच प्रत्याशियों की घोषणा बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर से ज्योति लोधी सीटों पर बातचीत के बीच हुई। यह संगठन की तैयारी हो सकती है, लेकिन सहयोगी को भरोसे में लिए बिना घोषणा दबाव की राजनीति लगती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दावों के बीच यह कदम और चुभता है। इमरान मसूद का आक्रोश इसी अपमानबोध से निकला है। उनका कहना है कि कांग्रेस भीख नहीं मांग रही और गठबंधन में सीटें दया से नहीं, आपसी सहयोग से तय होती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस ने सीटें मांगी ही नहीं तो 26 का आंकड़ा थोपने का अधिकार किसने दिया। सपा को समझना होगा कि सहयोगी को सार्वजनिक रूप से छोटा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। कांग्रेस भी बताए कि कमजोर संगठन वाली सीटों पर उसका दावा किस आधार पर है। ओमप्रकाश राजभर ने इमरान के बयान पर तंज कसते हुए पूछा कि यदि कांग्रेस भीख नहीं मांग रही तो सीटों पर बातचीत के लिए कमेटी लेकर सपा के पास क्यों गई। सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने भी कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे 50 सीटें देना भी बड़ी बात होगी। उन्होंने कांग्रेस के संगठन और उम्मीदवारों की क्षमता पर भी सवाल उठाए। ऐसे बयान बताते हैं कि भाजपा से मुकाबले की तैयारी कर रहे दोनों दलों के बीच भरोसे से ज्यादा एक-दूसरे की हैसियत नापने की होड़ लगी है।पांच नामों की सामाजिक बनावट भी संदेश देती है। चार मुस्लिम चेहरे और एक ओबीसी महिला उम्मीदवार के जरिए सपा मुस्लिम प्रतिनिधित्व और पिछड़े वर्ग की भागीदारी का दावा मजबूत करना चाहती है। पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तभी चलेगा जब गैर-यादव पिछड़ों और दलितों को टिकट, संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी मिले। मुस्लिम मतदाता भी सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और सम्मान चाहते हैं। ओवैसी की राजनीति मुस्लिम मतों में विकल्प का सवाल उठाती है, जबकि बसपा दलित मतों पर अपनी पकड़ लौटाने की कोशिश कर सकती है। सपा का गणित इन दोनों चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर प्रस्तावित पीडीए प्रणपत्र सपा की दूसरी बड़ी परीक्षा है। प्रदेश, 75 जिलों और लखनऊ के लिए अलग दस्तावेज बनाने की तैयारी स्थानीय मुद्दों को जगह देने का अवसर है। महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन, स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये सहायता, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीबों को मुफ्त इलाज जैसे प्रस्ताव चर्चा में हैं। ये संभावित वादे हैं, अंतिम घोषणाएं नहीं। लाभार्थियों की संख्या, सालाना खर्च और धन का स्रोत बताना होगा। डॉक्टर-दवा-बिस्तर के बिना मुफ्त इलाज कागज पर रहेगा। लखनऊ में मुफ्त मेट्रो यात्रा और जाम से राहत का वादा भी तभी सार्थक होगा जब परिवहन और बुनियादी ढांचे की ठोस योजना हो।भाजपा इस खींचतान को बैठे-बिठाए भुनाएगी। वह मुस्लिम उम्मीदवारों की सूची से ध्रुवीकरण कर गैर-यादव पिछड़ों, दलितों और लाभार्थियों में पकड़ मजबूत करेगी। उसे भी बेरोजगारी, महंगाई, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था पर जवाब देना होगा। विपक्षी बिखराव सवालों को मिटाता नहीं, उनकी आवाज दबाता है। 2017 का अनुभव दोनों दलों के सामने है। गठबंधन के बावजूद भाजपा ने 312 सीटें जीतीं, सपा 47 और कांग्रेस सात पर सिमट गई। वोट अपने आप एक-दूसरे को नहीं मिलते। 2024 का साझा प्रदर्शन उत्साह देता है, पर विधानसभा का मुकाबला अलग होगा। यदि सीटों पर सम्मानजनक समझौता हुआ, साझा उम्मीदवार और बूथ स्तर पर तालमेल बना तो लड़ाई कड़ी हो सकती है। यदि समझौता अपमान और मजबूरी में हुआ तो कार्यकर्ता भीतर से साथ नहीं देंगे। और यदि गठबंधन टूटा तो विपक्षी मतों का बंटवारा भाजपा की राह आसान करेगा। अखिलेश को तय करना है कि उन्हें कांग्रेस की जरूरत है या केवल कांग्रेस के नाम की। कांग्रेस को भी तय करना है कि वह जमीन पर ताकत बनाएगी या आंकड़ों से अपनी कीमत बढ़ाती रहेगी। अखिलेश को यह याद रखना होगा कि 2024 की सफलता में कांग्रेस के वोट और राहुल गांधी की सक्रियता का योगदान था। साझेदार की ताकत स्वीकारना कमजोरी नहीं, चुनावी समझदारी है। भाजपा को हराने के लिए अहंकार छोड़ना, ईमानदार समझौता करना और जनता को जवाब देना होगा। वरना विपक्ष हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ेगा, जबकि कारण आज की सौदेबाजी होगी।

अजय कुमार

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

मदिरालय में चिकित्सा, अस्पताल में प्रतीक्षा

जिस देश में मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के पीछे और डॉक्टर अपनी सुविधाओं के पीछे दौड़ता हो, वहां मध्यप्रदेश के सागर की पहल ने चिकित्सा का भूगोल ही बदल दिया। अब डॉक्टर अस्पताल में मरीज की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, बल्कि शराब की दुकान पर (और चिन्हित लोगों के घरों पर भी) ग्राहक/आदतन सेवन करने वालों का इंतजार करेंगे। आखिर सरकार भी क्या करे, जिसे अस्पताल तक लाना मुश्किल हो, उसे उसके पसंदीदा ठिकाने पर ही स्वास्थ्य का पाठ पढ़ा दिया जाए! मदिरा की दुकान के बाहर डॉक्टर बैठेंगे, ग्राहक बोतल खरीदने आएगा तो पहले उसकी सेहत का हाल पूछा जाएगा। सरकारी चिकित्सा ने मरीज तक पहुंचने का नया रास्ता खोज लिया है। बस, इलाज तक पहुंचने का रास्ता अभी तलाशना बाकी है।

आबकारी और स्वास्थ्य विभाग की इस संयुक्त पहल के तहत मदिरा दुकानों पर नियमित शराब सेवन करने वालों की पहचान की जा रही है। जो लोग स्वेच्छा से स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहते हैं, उनकी जांच की जा रही है। उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। पहल का विचार अपनी जगह ठीक है, लेकिन सरकारी व्यवस्था का यह प्रयोग कई सवाल भी खड़े करता है। अस्पतालों में मरीजों को डॉक्टर और सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ता है, मगर शराब की दुकान पर चिकित्सा की सुविधा खुद चलकर पहुंच गई। अब यह समझना मुश्किल है कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है या मरीजों की आदतों के हिसाब से सरकारी सुविधाओं के पते तय किए जा रहे हैं।

इस मुहिम की पृष्ठभूमि में जिले में बीते तीन महीनों के दौरान शराब सेवन के बाद हुई मौतों की घटनाएं हैं। हाल ही में सागर (मप्र) के बंडा में दो और देवरी में एक (कुल तीन) लोगों की मृत्यु हुई। जांच में सामने आया कि इनमें शराब की भूमिका तो थी, लेकिन कई पीड़ित पहले से लिवर-किडनी की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। यानी मौत का कारण बीमारी निकला, लेकिन व्यवस्था ने उसका समाधान मदिरा दुकान के बाहर खोजा। सवाल है कि जिन बीमारियों ने लोगों की जान ली, उनकी पहचान पहले क्यों नहीं हुई? क्या स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की व्यवस्था इतनी कमजोर है कि बीमारी को पकड़ने के लिए मरीज का शराब की दुकान तक पहुंचना जरूरी हो गया? मौत के बाद कारण तलाशने से बेहतर होता कि बीमारी को समय रहते पहचान लिया जाता।

सरकारी व्यवस्था का अपना एक दिलचस्प ढर्रा है। कोई घटना हुई, जांच बैठी, अधिकारियों ने निर्देश दिए और फिर एक नया अभियान शुरू हो गया। कुछ दिनों तक गतिविधियां चलती हैं, तस्वीरें सामने आती हैं और उपलब्धियों का ब्योरा तैयार हो जाता है। लेकिन समस्या की जड़ अक्सर वहीं पड़ी रहती है। यहां भी डॉक्टर दुकान के बाहर बैठ गए, मगर असली सवाल यह है कि जांच में किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी निकल आए तो आगे क्या होगा? क्या उसे अस्पताल में उपचार मिलेगा? क्या नियमित चिकित्सकीय परामर्श और निगरानी होगी? क्या शराब छोड़ने के इच्छुक लोगों को आवश्यक सहायता मिलेगी? केवल बीमारी बता देना इलाज नहीं है। वरना सरकारी रजिस्टर में स्वास्थ्य सुधरता रहेगा और मरीज अपनी बीमारी के साथ घूमता रहेगा।

इस पूरी कवायद में आबकारी और स्वास्थ्य विभाग की साझेदारी भी गौर करने लायक है। एक विभाग का संबंध मदिरा की बिक्री और राजस्व से है, दूसरे का काम नागरिक की सेहत बचाना है। एक ओर बिक्री का कारोबार है, दूसरी ओर नुकसान से बचने की सलाह। सरकार का यह दोहरा दृश्य अपने आप में व्यंग्य है। राजस्व की व्यवस्था भी चलती रहे और ग्राहक को स्वास्थ्य का महत्व भी समझाया जाता रहे। सवाल यह है कि क्या जनस्वास्थ्य की चिंता केवल मदिरा खरीदने वालों तक सीमित है? क्या राजस्व के साथ शराब सेवन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की भी कोई दीर्घकालीन योजना है? लोगों को नुकसान बताना पर्याप्त नहीं, उन्हें उससे बाहर निकलने का रास्ता देना भी जरूरी है।

यदि डॉक्टर शराब की दुकानों के बाहर पहुंच सकते हैं तो गांवों, मजदूर बस्तियों और दूरदराज के इलाकों में क्यों नहीं? मधुमेह, रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियां केवल शराब पीने वालों को नहीं होतीं। अनेक लोग समय पर जांच और उपचार न मिलने के कारण गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं। क्या उनकी सेहत की चिंता करने के लिए भी किसी अप्रिय घटना का इंतजार होगा? स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य मरीज को उसकी आदतों के ठिकाने पर पकड़ना नहीं, बल्कि बीमारी को गंभीर होने से पहले रोकना होना चाहिए।

इस पहल को खारिज करना उचित नहीं होगा। नियमित शराब सेवन करने वालों की जांच और जागरूकता उपयोगी कदम हैं, लेकिन इनका परिणाम उपचार और निरंतर परामर्श के रूप में दिखाई देना चाहिए। डॉक्टर की कुर्सी लगाना आसान है, स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियां दूर करना कठिन। अभियान की सफलता सुर्खियों या जांच के आंकड़ों से नहीं, बल्कि उन लोगों से तय होगी जिन्हें समय पर इलाज मिला। फिलहाल डॉक्टर मदिरा की दुकान पर ग्राहक की नब्ज टटोल रहे हैं। अच्छा है, लेकिन अब कोई सरकारी व्यवस्था की नब्ज भी टटोल ले। वहां बीमारी के लक्षण छिपे नहीं हैं—अस्पतालों की परेशानियां, उपचार की बाधाएं और समस्या आते ही अभियान शुरू करने की आदत। मरीज को अस्पताल तक लाने में नाकाम व्यवस्था अब डॉक्टर को शराब की दुकान तक ले आई है। विडंबना यह है कि ग्राहक अपनी बीमारी की जांच कराने को तैयार है, मगर व्यवस्था अपनी बीमारी मानने को तैयार नहीं।

प्रो. आरके जैन अरिजीत

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

दुखियारों को हमदर्दी के आँसू भी कम प्यारे नहीं होते।

: प्रेमचंद

कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो निर्धन हो जाता है।

: चाणक्य

सूडोकु नवताल- 7704

सरल

8	5			3		6	1	
6	7		9		4		2	
2					1			4
	3	9			7			
	6	2		8		4	7	
			6			9	3	
3			5					7
	4		1		6		8	3
	8	5		7			9	6

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7703 का हल

6	3	7	2	1	5	4	8	9
9	8	4	3	7	6	5	2	1
2	5	1	9	4	8	7	3	6
3	6	8	5	9	7	1	4	2
7	2	9	4	8	1	6	5	3
4	1	5	6	3	2	8	9	7
5	7	6	8	2	9	3	1	4
8	4	2	1	6	3	9	7	5
1	9	3	7	5	4	2	6	8

दैनिक पंचांग

26 नवम्बर 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति
सूर्य	वृश्चिक में
चंद्र	वृष में
मंगल	सिंह में
बुध	तुला में
गुरु	सिंह में
शुक्र	तुला में
शनि	मीन में
राहु	कुंभ में
केतु	सिंह में

राहुकाल 1.30 से 3.00 बजे तक

लग्नारंभ समय	
धनु	07.57 बजे से
मकर	10.02 बजे से
कुंभ	11.49 बजे से
मीन	13.22 बजे से
मेष	14.52 बजे से
वृष	16.32 बजे से
मिथुन	18.30 बजे से
कर्क	20.44 बजे से
सिंह	23.00 बजे से
कन्या	01.12 बजे से
तुला	03.23 बजे से
वृश्चिक	05.37 ब.से

गुरुवार 2026 वर्ष का 330 वा दिन **दिशाशूल** दक्षिण **ऋतु** हेमन्त। **विक्रम संवत्** 2083 **शक संवत्** 1948 **मास** मृगशीर्ष (दक्षिण भारत में कार्तिक) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** द्वितीया 13.16 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** मृगशीर्ष 17.47 बजे को समाप्त। **योग** सिद्ध 07.50 बजे तदनन्तर साध्य 03.45 बजे रात्र को समाप्त। **करण** गर 13.16 बजे तदनन्तर वणिज 23.31 बजे को समाप्त। **चन्द्रायु** 16.7 घण्टे **रवि क्रान्ति** दक्षिण 20° 54' **सूर्य** दक्षिणायन **कलि अहर्गण** 1872905 **जूलियन दिन** 2461370.5 **कलियुग संवत्** 5128 **कल्पारंभ संवत्** 1972949128 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885128 **वीरनिर्वाण संवत्** 2552 **हिजरी सन्** 1448 **महीना** जमादि उस्सानी **तारीख** 15

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
शुभ	05.54	07.22 बजे तक	अमृत	05.40	07.11 बजे तक
रोग	07.22	08.51 बजे तक	चर	07.11	08.43 बजे तक
उद्वेग	08.51	10.19 बजे तक	रोग	08.43	10.15 बजे तक
चर	10.19	11.47 बजे तक	काल	10.15	11.47 बजे तक
लाभ	11.47	01.15 बजे तक	लाभ	11.47	01.19 बजे तक
अमृत	01.15	02.43 बजे तक	उद्वेग	01.19	02.51 बजे तक
काल	02.43	04.11 बजे तक	शुभ	02.51	04.23 बजे तक
शुभ	04.11	05.40 बजे तक	अमृत	04.23	05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

राष्ट्र की आत्मा का प्रतिविम्ब है भारतीय संविधान

संविधान दिवस (26 नवंबर) केवल आधुनिक भारत के वैधानिक इतिहास की एक तिथि मात्र नहीं है, अपितु यह सहस्राब्दियों से प्रवहमान भारतीय राजनीतिक चिंतन और धर्म आधारित शासन व्यवस्था की शाश्वत परिणति का महापर्व है। पाश्चात्य जगत में जब राज्य की अवधारणा आदिम अवस्था में थी, तब आर्यावर्त के ऋषियों ने सभा, समिति और विदथ जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का न केवल सूत्रपात किया, अपितु राजा को भी धर्म अर्थात विधि के शासन के अधीन अनुशासित किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान सभा में इस सत्य को रेखांकित किया था कि भारत के लिए लोकतंत्र कोई नवीन आयातित वस्तु नहीं, अपितु हमारी प्राचीन वैदिक और बौद्ध परंपराओं की ही विरासत है। शाश्वत सत्य यही है कि किसी भी राष्ट्र का संविधान उसकी आत्मा का प्रतिबिंब होता है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने इस महान ग्रंथ को अंगीकृत किया, तो वस्तुतः वह प्राचीन ऋषियों के सर्वे भवन्तु सुखिनः के संकल्प को आधुनिक संवैधानिक भाषा में रूपांतरित करने का पुनीत अनुष्ठान था। भारतीय संवैधानिक परंपरा का आदि स्रोत चारों वेद हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है-

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने।

यहां समिति संपूर्ण प्रजा की प्रतिनिधि महासभा थी, जो राजा के निर्वाचन और नीति निर्धारण का अधिकार रखती थी, जबकि सभा विद्वानों और न्यायविदों की एक उच्च परिषद् थी, जो आधुनिक राज्यसभा और सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष कार्य करती थी। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में लोकतांत्रिक संवाद और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का अद्भुत शंखनाद सुनाई देता है-

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।।

इसका भावार्थ है कि नागरिकों का विचार-विमर्श एक हो, उनकी समिति (संसद) एक हो, और उनका चित्त एवं संकल्प समान हो। आधुनिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित बंधुता, विचार की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के आदर्श इसी वैदिक ऋचा के शाश्वत विस्तार हैं। वैदिक युग में राजा निरंकुश नहीं था। बृहदारण्यक उपनिषद में विधि की सर्वोच्चता को स्पष्ट करते हुए कहा गया है-

तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मः तस्माद्धर्मात्परं नास्ति अथो अबलीयान् बलीयांसमाशास्ते धर्मेण यथा राज्ञा।

अर्थात -धर्म (विधि) राजाओं का भी राजा है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उसी विधि के बल से एक निर्बल व्यक्ति भी शक्तिशाली से न्याय की अपेक्षा कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 14, जो विधि के समक्ष समता प्रदान करता है, इसी शाश्वत सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप है।

महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण और महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत भारतीय राजनीतिशास्त्र के विश्वकोश हैं। रामायण में चित्रित रामराज्य आधुनिक संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जीवंत आदर्श है। अयोध्याकाण्ड के कच्चित् सर्ग में श्रीराम भरत से शासन व्यवस्था के जो प्रश्न पूछते हैं- जैसे कृषकों की सिंचाई व्यवस्था, लोककल्याण में राजकोष का व्यय और निर्दोष की रक्षा, वे किसी भी लोकतांत्रिक संविधान की कसौटी हैं। रामराज्य में शासक का व्यक्तिगत सुख प्रजा के सुख के समक्ष गौण है। आधुनिक संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75) इसी राजधर्म की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। महाभारत के शांतिपर्व में भीष्म पितामह स्पष्ट करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति अराजकता (मात्स्यन्याय) को समाप्त करने और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुई थी। महाभारत का यह निर्देश कि प्रजा की रक्षा करने में विफल राजा को प्रजा द्वारा त्याग देना चाहिए, आधुनिक विचारकों के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से सहस्रों वर्ष पूर्व प्रतिपादित हो चुका था। इसके अतिरिक्त, शांतिपर्व में गणराज्यों (अंधक, वृष्णि, यौधेय आदि) के संचालन के सूक्ष्म नियमों का वर्णन है, जहां भीष्म चेतावनी देते हैं कि गणराज्यों का विनाश आंतरिक फूट और गुप्त मंत्रणा भंग होने से होता है। यह चेतावनी आज के बहुदलीय लोकतंत्र के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र भारत का प्रथम व्यवस्थित शासन विधान है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत (स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र) का प्रतिपादन किया। उन्होंने राजा के कर्तव्यों को सूत्रबद्ध करते हुए लिखा-

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

अर्थात- प्रजा के सुख और हित में ही राजा का वास्तविक सुख और हित है। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार निवारण, लोककल्याणकारी कर प्रणाली और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर कठोर नियम बनाए। अर्थशास्त्र में पक्षपात करने वाले न्यायाधीशों के लिए भी दंड का प्रावधान था, जो न्यायिक जवाबदेही का प्राचीनतम उदाहरण है। इसी प्रकार, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में दीवानी (व्यवहार) और फौजदारी (कंटकशोधन) कानूनों, संपत्ति के अधिकार, स्त्रीधन और अनुबंध विधि के जो नियम प्रतिपादित किए गए, वे आधुनिक भारतीय विधि व्यवस्था के मूल आधारों में विद्यमान हैं।

भारतीय संसद की कार्यप्रणाली- जैसे कोरम (गणपूर्ति), प्रस्ताव, तीन वाचन और मतदान, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध संघों और लिच्छवि, शाक्य, वज्जि आदि गणराज्यों में पूर्ण रूप से प्रचलित थी। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक और महापरिनिब्बान सुत्त में तत्कालीन संथागार (संसद भवन) के कठोर नियमों का विवरण मिलता है-

आसनप्रज्ञापक- सदस्यों को वरिष्ठता के अनुसार स्थान आवंटित करने वाला अधिकारी।

गणपूर्ति- बैठक की वैधता के लिए न्यूनतम सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति।

ज्ञप्ति और अनुसावन- प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करना ज्ञप्ति और महत्वपूर्ण विधेयकों को तीन बार पढ़ना ज्ञप्तिचतुर्थ कर्म कहलाता था। आधुनिक संसद में किसी विधेयक के तीन वाचन की प्रणाली इसी का अनुकरण है।

शलाका ग्रहण -सर्वसम्मति के अभाव में लकड़ी की शलाकाओं (मतपत्रों) से मतदान होता था, जिसमें गुप्त मतदान (गूढ़क) और खुला मतदान (विवतक) दोनों प्रचलित थे।

डॉ. अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इन बौद्ध संघों का गौरवपूर्ण उल्लेख करते हुए कहा था कि भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं किसी विदेशी राष्ट्र से नहीं सीखीं, अपितु यह हमारी अपनी ही विरासत है।

संविधान निमार्ताओं ने विश्व के प्रमुख संविधानों के श्रेष्ठ तत्वों का अध्ययन करते हुए इसकी आत्मा को पूर्णतः भारतीय रखा। आचार्य नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत संविधान की मूल पांडुलिपि में भारतीय सभ्यता की अविच्छिन्न यात्रा अंकित है। मौलिक अधिकारों (भाग-3) के शीर्ष पर श्रीराम के अयोध्या आगमन का चित्र मर्यादापूर्ण शासन का प्रतीक है, तो नीति निदेशक तत्वों (भाग-4) पर श्रीकृष्ण के गीता उपदेश का चित्र निष्काम कर्म का संदेश देता है। मोहनजोदड़ो, वैदिक गुरुकुल, बुद्ध, महावीर, अशोक, विक्रमादित्य, नालंदा, शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के चित्र प्रमाणित करते हैं कि हमारा संविधान हमारी पांच सहस्र वर्ष की सभ्यता का आधुनिक संस्करण है। हम भारत के लोग संप्रभुता को संपूर्ण जनता में निहित करता है। प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता भारतीय दर्शन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय का आधुनिक सामाजिक रूपांतरण हैं। भारतीय दर्शन में कर्तव्य पालन से ही अधिकारों की रक्षा होती है। गीता के कर्मयोग और वैदिक पृथ्वी सूक्त (माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः) की भावना ही अनुच्छेद 51 (क) के मौलिक कर्तव्यों में प्रतिबिंबित होती है।

पाश्चात्य सेकुलरिज्म के विपरीत भारतीय पंथनिरपेक्षता ऋग्वेद के एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति और सम्राट अशोक की सर्वधर्म समभाव की नीति पर आधारित है। वहीं अनुच्छेद 40 और 73वें-74वें संशोधन द्वारा स्थापित पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन चोल साम्राज्य की कुडवोलाई (ग्राम सभा चुनाव) और वैदिक ग्रामणी व्यवस्था का पुनर्जागरण है। भारतीय संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं, अपितु समय के साथ विकसित होने वाला एक जीवंत वृक्ष है। जिस प्रकार प्राचीन भारत में श्रुति (वेद) के शाश्वत सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखते हुए देश काल के अनुसार स्मृतियों में परिवर्तन होते रहे, उसी प्रकार हमारा संविधान अपने मूल ढांचे (इंदू रश१४३४१) को सुरक्षित रखते हुए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया से निरंतर गतिशील है। 1973 के केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढां

वाराणसी में 28 नवंबर से शुरू होगा काशी तमिल संगमम 5.0

एजेंसी, वाराणसी



- तमिलनाडु से 1,400 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा

तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के काशी के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषायी और सभ्यतागत संबंधों को नई मजबूती देने वाला काशी तमिल संगमम का पांचवां संस्करण 28 नवंबर से वाराणसी में शुरू होगा। 12 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन की थीम 'तिरुक्कुरल पाईलवोम-तिरुक्कुरल का अभ्यास करें' रखी गई है। इसके माध्यम से युवा पीढ़ी और देशभर के विद्यार्थियों को तमिल के महान शास्त्रीय ग्रंथ तिरुक्कुरल की नैतिक शिक्षाओं और जीवन मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

आयोजन में तमिलनाडु से करीब 1,400 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ये प्रतिनिधि वाराणसी के साथ प्रयागराज और अयोध्या का भी भ्रमण करेंगे। इस दौरान शैक्षणिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठियां, संवाद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आपसी समझ तथा सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ किया जाएगा। काशी तमिल संगमम 5.0 के तहत देश के 1,000 उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर छात्र सहभागिता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक विषयों और भाषायी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के बीच तिरुक्कुरल की व्यापक समझ विकसित करना है। इसके तहत संरचित अध्ययन, शोध और परिसर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

प्रत्येक भागीदार संस्थान तिरुक्कुरल में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर मेरिट के आधार पर एक छात्र का चयन करेगा। चयनित विद्यार्थियों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और अंग्रेजी में ऑनलाइन शैक्षणिक अभिमुखीकरण दिया जाएगा। इसके बाद एक महीने तक शोध एवं शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। इसके लिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) की ओर से बहुभाषी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम की निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले प्रत्येक पात्र चयनित विद्यार्थी को 10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति (स्टाइपेंड) भी दी जाएगी। विद्यार्थियों को संकाय मार्गदर्शक की देखरेख में चार से दस पृष्ठों का शोध लेख या शोध नोट तैयार करना होगा। साथ ही अपने संस्थान में तिरुक्कुरल विषय पर एक घंटे की प्रस्तुति भी देनी होगी। काशी तमिल संगमम के दौरान तमिलनाडु के 50 शिक्षक उत्तर प्रदेश आएंगे। ये शिक्षक राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को तिरुक्कुरल की शिक्षाओं से परिचित कराएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु के विशेषज्ञ वाराणसी के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कक्षाएं और संवाद सत्र आयोजित करेंगे। विद्यार्थियों को ओरिएंटेशन मॉड्यूल, संवादात्मक सत्रों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से तिरुक्कुरल के नैतिक, सामाजिक और जीवनोपयोगी मूल्यों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य इस प्राचीन तमिल ग्रंथ की शिक्षाओं को युवाओं के दैनिक जीवन से जोड़ना है।

पासपोर्ट में जन्म स्थान पर सवाल उठने पर सौरभ दास से स्पष्टीकरण मांगा गया: विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास के पासपोर्ट में दी गई जन्मस्थान की जानकारी को लेकर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने प्रश्न खड़ा किया था जिसके बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनसे कहा गया है कि स्पष्टीकरण मिलने तक वे अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल न करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में एक प्रश्न पर कहा कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपेक्षा की जाती है कि आवेदक सही जानकारी दें। इसमें कमी या त्रुटि पाए जाने पर आवेदक को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है।

चेन्नई के क्षेत्रीय कार्यालय से आधिकारिक जानकारी मिलने पर नोटिस दिया गया है। सौरभ दास को सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है और जवाब मिलने तक पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। उल्लेखनीय है कि सौरभ दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोका गया था। उनके पासपोर्ट में जन्म स्थान को लेकर जांच जारी है।

प्रणब मुखर्जी के मुद्दे पर वह अनावश्यक चर्चा नहीं चाहते हैं : शुभेंदु अधिकारी

एजेंसी, कोलकाता



पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सलाह पर तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के अपने बयान पर छिड़ी राजनीतिक बहस के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस विषय को विराम देने की अपील की है। बुधवार को कूचबिहार के रास मेले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में इस मुद्दे पर अब और 'अनावश्यक चर्चा' नहीं चाहते।

उल्लेखनीय है कि, एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सलाह पर उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। उन्होंने बताया कि जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तब वे तृणमूल में रहते उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन गए थे। उस समय प्रणब मुखर्जी ने उन्हें तृणमूल छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने की सलाह दी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने उनसे कहा था, "यदि कर्मचारी बनकर रहना है तो तृणमूल में रहो और यदि अपने दम पर आगे बढ़ना है तो मोदीजी के साथ रहो।" अपनी पूर्व पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बारे में पूछे जाने पर शुभेंदु ने उसे एक 'कंपनी' की संज्ञा देते हुए कहा था कि वे वहां केवल एक कर्मचारी थे और दिवंगत प्रणब मुखर्जी उनके असली मार्गदर्शक थे।

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में बहस तेज हो गई थी कि आखिर किस समय प्रणब मुखर्जी ने उन्हें यह सलाह दी होगी। बुधवार को कूचबिहार रास मेले में जब इस संदर्भ में उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने इस पर आगे चर्चा न करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रणब बाबू अब ईश्वर लोक जा चुके हैं। वे हमारे बीच नहीं हैं। वे एक महामानव थे। मेरी बातों पर कई लोग विवाद खड़ा कर सकते हैं। वे परम सम्माननीय व्यक्ति हैं और मैं नहीं चाहता कि इस विषय पर अब कोई अनावश्यक चर्चा हो।

गौरतलब है कि, प्रणब मुखर्जी वर्ष 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे। इस पूरे कार्यकाल के दौरान शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में ही थे और राज्य मंत्रिमंडल सहित पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। बाद में दिसंबर, 2020 में मेदिनीपुर में अमित शाह की जनसभा के दौरान वे औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुए थे। इससे कुछ समय पहले ही प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति के साथ शुभेंदु अधिकारी के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने स्वयं अपना प्रमुख मार्गदर्शक बताया है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में भी शुभेंदु की प्रशंसा की थी।

संक्षिप्त समाचार

प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो के सिर सजा मिस यूनिवर्स 2026 का ताज

सैन जुआन (प्यूर्टो रिको)। प्यूर्टो रिको की 27 वर्षीय जेनिफर बैरेटो ने मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया । सैन जुआन में आयोजित प्रतियोगिता के 75वें संस्करण में 116 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया, लेकिन जेनिफर ने अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन से सभी को पीछे छोड़ दिया। उन्हें वर्ष 2025 की मिस यूनिवर्स विजेता मेक्सिको की फातिमा बॉश ने ताज पहनाया। इस बार प्रतियोगिता का आयोजन प्यूर्टो रिको के सैन जुआन स्थित जोस मिगुएल एग्रेलोट कोलिजियम में किया गया। कई हफ्तों तक चली इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों की संस्कृति और प्रतिभा की झलक देखने को मिली। इस साल प्रतियोगिता के 75वें संस्करण के मौके पर एक खास ताज भी पेश किया गया। 'द रेडियंस ऑफ एन इटरनल लेगेसी' नाम के इस ताज को ज्वेलरी डिजाइनर जॉर्ज विटल्स ने पेरिस के ज्वेलरी हाउस 'मेसन डी'ओर' के साथ मिलकर तैयार किया । 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बने इस ताज में 3,150 हीरे जड़े गए हैं। हालांकि, इस बार की प्रतियोगिता केवल अपनी भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि विवादों के कारण भी चर्चा में रही। वीजा संबंधी परेशानियों और फ्रेंचाइजी विवादों के चलते कुछ देशों की प्रतिभागियों को प्रतियोगिता से हटना पड़ा। वहीं, इजराइल की प्रतिभागी की नेशनल कॉस्ट्यूम को लेकर भी सोशल मीडिया पर विरोध देखने को मिला। भारत के केरल की 19 वर्षीय काजिया लिज मेजो ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने टॉप-30 में जगह बनाकर देश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन स्विमसूट राउंड के बाद टॉप-12 में पहुंचने से चूक गईं। मॉडल होने के साथ कानून की छात्रा काजिया ने इसी साल मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता था। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली केरल की पहली महिला बनी थीं। इससे पहले 2024 में उन्होंने मिस टीन दिवा का खिताब जीता था और 2025 में मिस टीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए फर्स्ट रनर-अप रही थीं।

काठमांडू एयरपोर्ट पर 2.34 किलो संदिग्ध सोने के साथ दो चीनी महिलाएं गिरफ्तार, शरीर के अंदर छिपाकर लाई थीं

काठमांडू। नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने जैसी दिखने वाली पीले रंग की अर्धठोस धातु के साथ दो चीनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। बरामद पदार्थ का कुल वजन 2 किलो 348 ग्राम बताया गया है। दोनों महिलाएं इसे अपने शरीर के मलद्वार और अंतर्वस्त्रों में छिपाकर हांगकांग से काठमांडू लाई थीं। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों महिलाओं को सीमा शुल्क क्षेत्र पार कर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के दौरान संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों महिलाएं मंगलवार देर रात 11:15 बजे कैथे पैसिफिक एयरलाइंस की उड़ान से हांगकांग से काठमांडू पहुंची थीं। उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की। तलाशी के दौरान उनके मलद्वार और अंतर्वस्त्रों के भीतर प्लास्टिक में लपेटकर छिपाए गए सोने जैसे दिखने वाले पीले रंग के अर्धठोस पदार्थ के आठ गोलाकार टुकड़े बरामद किए गए। प्लास्टिक रैप सहित इनका कुल वजन 2 किलो 348 ग्राम पाया गया। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान चीन के गुआंगडोंग प्रांत की 45 वर्षीय लिन लिना और 35 वर्षीय लिन जिनपिंग के रूप में हुई है। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सुरक्षा कार्यालय के सह-प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक दुण्डीराज न्यौपाने के अनुसार, दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर आवश्यक जांच की जा रही है। उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए मंगलवार को ही त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल सीमा शुल्क कार्यालय को सौंपने की जानकारी पुलिस ने दी है। बरामद पीले अर्धठोस पदार्थ की वास्तविक प्रकृति और उसमें सोने की मात्रा की आधिकारिक पुष्टि इस प्रेस विज्ञप्ति में नहीं की गई है।



माटी कला के लाइव डेमो से लेकर आकर्षक छूट तक, दर्शकों को लुभा रहा झारखंड पवेलियन

नई दिल्ली। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) में झारखंड पवेलियन में माटी कला बोर्ड द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने की लाइव डेमो प्रस्तुति लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चाक पर मिट्टी को आकार देकर पारंपरिक तकनीक से सुंदर कलाकृतियां तैयार करते कारीगरों को देख दर्शक इस कला को करीब से समझने और जानने में रुचि दिखा रहे हैं। इस अवसर पर हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विभाग की निदेशक प्रीति रानी ने मिट्टी के बर्तन बनाने की लाइव डेमो प्रस्तुति में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वयं चाक पर मिट्टी को आकार देकर झारखंड की पारंपरिक माटी कला का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की मिट्टी में यहां की संस्कृति, परंपरा और स्थानीय कारीगरों की रचनात्मकता की अनूठी पहचान समाहित है। माटी कला केवल एक शिल्प नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह के लाइव डेमो से लोगों को स्थानीय कलाकारों की मेहनत और हुनर को करीब से जानने का अवसर मिलता है। मेले के समापन के करीब पहुंचने के साथ ही झारखंड पवेलियन के विभिन्न स्टॉलों पर खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छूट भी दी जा रही है। कई स्टॉलों पर चयनित उत्पादों की खरीद पर 20 से 30 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध है। इससे आगंतुक झारखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक वस्तुओं की खरीदारी आकर्षक कीमतों पर कर सकते हैं। झारखंड पवेलियन में कला, संस्कृति, पारंपरिक हुनर और किफायती खरीदारी का यह संगम मेले के अंतिम दिनों में भी आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है।

असम में बनेंगी भारत की प्रमुख मिसाइलें, जागीरोड में स्थापित होगा डिफेंस पार्क : डॉ. हिमंत

एजेंसी, गुवाहाटी



असम में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। राज्य में भारत द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि जागीरोड में डिफेंस पार्क स्थापित करने की योजना है। इसके लिए सरकार ने करीब 6000 बीघा जमीन आवंटित की है। यह परियोजना जागीरोड स्थित सेमीकंडक्टर परियोजना के सामने विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के निर्माण में समय लगेगा, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में एक सपना देखा है और इसे साकार करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी बीच, राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत रंगिया के तुलसीबाड़ी में एकीकृत रक्षा उपकरण निर्माण एवं उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का भूमि पूजन किया।

सरकार ने इस परियोजना के लिए तुलसीबाड़ी स्थित एआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में 15 एकड़ जमीन आवंटित की है। स्पीड 4 डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इस केंद्र की स्थापना करेगा। यहां ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम, बंकर तथा अन्य रक्षा संबंधी उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना असम को रक्षा उत्पादन और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

तमिलनाडु : कार्तिकई महादीप नहीं जलाए जाने के मामले में जिला कलेक्टर ने दाखिल की रिपोर्ट

एजेंसी, मदुरै



तमिलनाडु के तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी स्थित दीप स्तंभ पर कार्तिकई महादीप नहीं जलाए जाने के मामले में मदुरै के जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा ने उच्चतम न्यायालय में 17 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में उन्होंने दीप नहीं जल पाने के लिए मंदिर देवस्थानम को जिम्मेदार ठहराया है। कलेक्टर के अनुसार, जिला प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कराने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए थे, लेकिन देवस्थानम की ओर से आवश्यक समिति के सदस्यों के नामों की सिफारिश नहीं की गई।

उच्चतम न्यायालय में 25 नवंबर, 2026 को दाखिल रिपोर्ट में जिला कलेक्टर ने बताया कि दीप स्तंभ पर दीप जलाने की जिम्मेदारी मंदिर देवस्थानम को सौंपी गई थी। इसके लिए अधिकतम 10 सदस्यों वाली समिति गठित की जानी थी, लेकिन देवस्थानम ने समिति के सदस्यों के नामों की सिफारिश नहीं की। जिला कलेक्टर के मुताबिक, देवस्थानम की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद दीप स्तंभ पर कार्तिकई महादीप नहीं जलाया जा सका। रिपोर्ट में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 20 नवंबर को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसके बाद 21 नवंबर को हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त और पुलिस आयुक्त के साथ परामर्श बैठक आयोजित की गई।

इसके अलावा तिरुपरंकुंद्रम तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक भी हुई। इन बैठकों में उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रत्येक पहलू पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि देवस्थानम की मंजूरी से अधिकतम 10 सदस्यों की समिति के माध्यम से दीप जलाने की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर की परंपराओं के अनुसार दीप जलाने की प्रक्रिया मंदिर के कार्यकारी अधिकारी निर्धारित करेंगे।

जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, दीप जलाने के कार्यक्रम के लिए सीआरपीएफ जवानों की तैनाती जरूरी नहीं थी। पुलिस आयुक्त ने भी स्पष्ट किया था कि तमिलनाडु पुलिस की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती है। बताया कि गत 24 नवंबर को देवस्थानम की कार्यकारी समिति को निर्देश दिया गया था कि दीप जलाने का कार्य केवल देवस्थानम द्वारा स्वीकृत समिति के सदस्य ही करें और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दीप स्तंभ पर दीप जलाने के समर्थन और विरोध में विभिन्न संगठनों के बड़ी संख्या में जुटने की संभावना थी। प्रशासन को प्रदर्शन और अप्रिय घटनाओं की आशंका से जुड़ी सूचनाएं मिली थीं। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मदुरै जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी।

तेल आयात के बिल में 25 फीसद हिस्सेदारी वाले वाणिज्यिक वाहनों पर अब चलेगा बिजली का जोर

एजेंसी, चेन्नई



- इलेक्ट्रिक ट्रकों की राह आसान करने के लिए आईआईटी मद्रास में राष्ट्रीय मंथन 21-22 जनवरी को

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में एक है आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता। देश की सड़कों पर दौड़ने वाले मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन इस चुनौती को और गंभीर बनाते हैं। माल ढुलाई और यात्री परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये वाहन देश के सड़क परिवहन की कुल ईंधन खपत का लगभग 40 प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं और भारत के कुल तेल आयात बिल में करीब 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं।

दरअसल, इसके बावजूद इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता अभी बेहद सीमित है। इलेक्ट्रिक ट्रक फिलहाल कुल वाणिज्यिक वाहन बिक्री का महज 0.2 प्रतिशत हैं। ऐसे में परिवहन क्षेत्र के विद्युतीकरण को गति देना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात में कमी और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है। इसी चुनौती का व्यावहारिक समाधान तलाशने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास 21 और 22 जनवरी 2027 को दो दिवसीय राष्ट्रीय संवाद 'ईसीवी डायलॉग' आयोजित करेगा। जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, वाहन निर्माता, लॉजिस्टिक्स कंपनियां, वाणिज्यिक बेड़ा संचालक और वैज्ञानिक एक मंच पर बैठकर इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने की बाधाओं, चार्जिंग नेटवर्क, वित्तपोषण और तकनीकी मानकों पर मंथन करेंगे। इस संवाद का लक्ष्य देश में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक परिवहन को गति देने के लिए ठोस नीतिगत सिफारिशें और राष्ट्रीय रोडमैप तैयार करना है।

तेल आयात और परिवहन की चुनौती का सीधा संबंध: भारत में सड़क परिवहन अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। कृषि उत्पादों से लेकर औद्योगिक कच्चे माल, उपभोक्ता वस्तुओं और निर्माण सामग्री तक की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा ट्रकों और दूसरे वाणिज्यिक वाहनों पर निर्भर है।

देश के भीतर माल की आवाजाही जितनी बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से परिवहन क्षेत्र की ईंधन आवश्यकता भी बढ़ रही है। मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन इस पूरी व्यवस्था में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि लंबी दूरी तक भारी माल ढोने के लिए इनका व्यापक इस्तेमाल होता है। आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामाकोटी ने इस चुनौती को रेखांकित करते हुए बताया कि भारत के सड़क परिवहन की ईंधन खपत में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है।

ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने की कवायद

एजेंसी, नई दिल्ली



केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में बुधवार को यहां जल शक्ति मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी, जल शक्ति राज्यमंत्री वी. सोमन्ना तथा दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्रालय के मुताबिक इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं के नियमित संचालन एवं रखरखाव के लिए स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

समझौते के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के प्रभावी संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कार्यबल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की निरंतरता, कार्यक्षमता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में मोदी सरकार की यह पहल महत्वपूर्ण है। यह समझौता ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा।

सिरसा ने नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पंजाब सरकार के दावे पर उठाए सवाल

एजेंसी, नई दिल्ली



पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राज्य की आम आदमी पार्टी (आआपा) सरकार की ओर से जारी आंकड़ों पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाए हैं। सिरसा ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने 632 दिनों में नशे से जुड़े मामलों में 94,746 लोगों की गिरफ्तारी का आंकड़ा पेश किया है, लेकिन यह आंकड़ा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। उन्होंने पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के बयान का जिक्र करते हुए सरकार के दावे को चुनौती दी। भाजपा मुख्यालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिरसा ने आरोप लगाया कि आआपा सरकार नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय छोटे अपराधों में मामले दर्ज कर रही है, ताकि आरोपियों को बाद में जमानत मिल सके। यदि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वास्तव में नशा तस्करी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया होता तो उन्हें इतनी आसानी से जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिलता।

सिरसा ने पंजाब की जेलों की कुल क्षमता का हवाला देते हुए सरकार के गिरफ्तारी संबंधी आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब की जेलों में लगभग 26 हजार कैदियों को रखने की क्षमता है, जबकि सरकार 632 दिनों में करीब 94 से 95 हजार लोगों को नशे से जुड़े अपराधों में गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि यदि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नशा तस्करी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, तो वे सभी जेलों में क्यों नहीं हैं? उन्होंने दावा किया कि वास्तविक नशा तस्करी के मामलों में आरोपियों के लिए जमानत हासिल करना आसान नहीं होना।

पूर्वोत्तर में भूकंप का कितना होगा कंपन, आईआईटी गुवाहाटी ने खोजा आकलन का नया विज्ञान

एजेंसी, नई दिल्ली



- 1200 वर्षों के करीब छह हजार भूकंपों का विश्लेषण कर विकसित की नई तकनीक

हिमालय की तलहटी से लेकर इंडो-बर्मा पर्वतमाला तक फैला पूर्वोत्तर भारत देश के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में शामिल है। 1897 के शिलांग और 1950 के असम भूकंप इस क्षेत्र की भूगर्भीय संवेदनशीलता की भयावह याद दिलाते हैं। अब आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक नई गणितीय पद्धति विकसित की है, जिससे भविष्य में भूकंप के दौरान जमीन कितनी तीव्रता से कांप सकती है, इसका अधिक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा। दरअसल, 1200 वर्षों के भूकंपीय इतिहास और लगभग छह हजार भूकंपों के रिकॉर्ड का विश्लेषण कर तैयार की गई इस तकनीक से आठ प्रमुख शहरों में संभावित भू-कंपन का आकलन किया गया है। अध्ययन में इम्फाल सबसे अधिक संवेदनशील शहर के रूप में सामने आया है। आईआईटी गुवाहाटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अभिषेक कुमार और उनके शोधार्थी रहे डॉ. निरंजन बोराह (वर्तमान में बराक वैली इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर) ने यह अध्ययन किया है। शोध के निष्कर्ष प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका जर्नल ऑफ सीस्मोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। प्रोफेसर अभिषेक कुमार कहते हैं, "भूकंप कब और कहां आएगा, इसकी निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। हमारा उद्देश्य संभावित भूकंप के दौरान जमीन के कंपन की तीव्रता का अनुमान लगाना है, ताकि निर्माण और आपदा प्रबंधन की तैयारियां अधिक वैज्ञानिक हो सकें।"

ऐतिहासिक आंकड़ों की अनिश्चितता को भी शामिल किया: पूर्वोत्तर दो प्रमुख विवर्तनिक सीमाओं के बीच स्थित है। भारतीय प्लेट की गतिविधियां, हिमालयी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, इंडो-बर्मा पर्वतमाला और शिलांग पठार की जटिल भूगर्भीय संरचना यहां भूकंपीय गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। कई सक्रिय भूगर्भीय भ्रंश खतरे को और बढ़ाते हैं। 12 जून 1897 का शिलांग भूकंप और 15 अगस्त 1950 का 8.6 तीव्रता वाला महान असम भूकंप इस क्षेत्र की विनाशकारी क्षमता के बड़े उदाहरण हैं। 1950 का भूकंप भारतीय उपमहाद्वीप में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंपों में गिना जाता है। प्रोफेसर कुमार बताते हैं, "भूकंपीय खतरे का आकलन करते समय ऐतिहासिक आंकड़ों की अनिश्चितता को शामिल करना बेहद जरूरी है। यदि किसी पुराने भूकंप के स्थान या परिमाण का निर्धारण पूरी तरह सही नहीं है तो उस पर आधारित भविष्य के खतरे का अनुमान भी प्रभावित हो सकता है।" इसी समस्या के समाधान के लिए शोध दल ने मूल सूची के आधार पर 200 कृत्रिम भूकंप सूचियां तैयार कीं।

26-11-2026 T.P. Page 8_Layout 1 26-11-2026 09:17 Page 1



कैसे बनते हैं डॉक्टर

डॉक्टर बनना निस्संदेह सबसे अधिक मांग वाले प्रोफेशन में से एक है। डॉक्टरों की मांग न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में है। यह पेशा न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि डॉक्टरों की तरफ से समाज में दिए गए योगदान के कारण महान माना जाता है। भारत में एमबीबीएस की डिग्री अक्सर पेशे से संबंधित होती है, लेकिन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए इस कोर्स को करने के अलावा और भी बहुत कुछ जरूरी है.....

भारत में वर्तमान में क्या है डॉक्टरों की स्थिति

भारत में सरकारी और निजी दोनों संस्थान/विश्वविद्यालय हैं, जो एमबीबीएस कराते हैं। देश में इस समय एमबीबीएस की सीटों की कुल संख्या 1,07000 से कुछ अधिक है। वहीं, इन सीटों पर प्रवेश के लिए लगभग हर वर्ष 20 लाख छात्र NEET UG परीक्षा देते हैं। हालांकि, सिर्फ 5 प्रतिशत अभ्यर्थियों को ही क्वालिफाई किया जाता है।

क्या है एडमिशन का नियम

नीट यूजी परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित राज्य की अथॉरिटी की तरफ से आयोजित होने वाली काउंसलिंग में भाग लेना होता है। क्योंकि राज्य कोटे की सीटों पर राज्य अथॉरिटी की तरफ से एडमिशन दिया जाता है। जबकि केंद्र कोटे की सीटों पर एमसीसी की तरफ से काउंसलिंग आयोजित की जाती है। एमबीबीएस भारत में 5.5 वर्ष का है, जिसमें 4.5 वर्ष का पाठ्यक्रम और एक वर्ष की इंटर्नशिप शामिल है।

एम्स जैसे संस्थानों में पीजी के लिए देना होता है ये एग्जाम

एम्स दिल्ली जैसे भारत के कुछ पुराने कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए INICET (राष्ट्रीय महत्व संस्थान सामान्य प्रवेश परीक्षा) आयोजित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली पीजी पाठ्यक्रमों जैसे मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस), डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी), मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस), डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। हर वर्ष करीब 2 लाख छात्र NEET PG और INICET देते हैं। सफल होने वाले छात्रों को 60,000 PG सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। वहीं, पीजी के बाद सर्जरी आदि में स्पेशलाइजेशन के लिए स्टूडेंट्स नीट एसएस आदि का एग्जाम दे सकते हैं।

सैलरी

MBBS, एमडी और सुपरस्पेशियलिटी के डॉक्टरों को लाखों रुपये की सैलरी दी जाती है। हालांकि, प्रैक्टिस के लिए उन्हें FMGE का एग्जाम देना होता है। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है।



एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर के रुप में चुनें करियर

यदि आप आसमानी ट्रैफ़िक को सुरक्षित रखने में रुचि रखते हैं और हवाई यातायात की गति पर नज़र रखने का चुनौतीपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, तो एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर या एटीसी के रुप में करियर विकल्प चुन सकते हैं। एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर या एटीसी टकराव को रोकने के लिए और यातायात की भीड़ से उत्पन्न होने वाली देरी को कम करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं और नीतियों के अनुसार हवाई अड्डे के आसपास और भीतर हवाई यातायात को नियंत्रित करते हैं।

एक हवाई यातायात नियंत्रक हवाई यातायात के सुरक्षित, व्यवस्थित और कुशल आवागमन के लिए और हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्र में जिम्मेदार होता है। नियंत्रकों के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन वे विमानों को भी आसानी से निर्देशित करते हैं ताकि देरी को कम किया जा सके, नामित हवाई अड्डों के माध्यम से हवाई अड्डे के यातायात को विनियमित किया जा सके और हवाई अड्डे के आगमन और प्रस्थान को विनियमित किया जा सके।

बहुत व्यस्त हवाई अड्डों में, हवा नियंत्रकों और जमीन नियंत्रकों के बीच काम विभाजित है। लैंडिंग के दौरान एयर नियंत्रक विमान का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि ग्राउंड कंट्रोलर रनवे पर विमानों का प्रबंधन करते हैं, पार्किंग स्टैंड और होल्डिंग क्षेत्रों से विमानों को टैक्सी के रूप में निर्देश जारी करते हैं।

वायु यातायात नियंत्रकों की भूमिका

- आने और प्रस्थान करने वाले विमानों से रेडियो कॉल करना।
- लैंडिंग और टेक-ऑफ निर्देश और सूचना जारी करना।
- टेलीफोन या अंतर-फोन का उपयोग करके, हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र से आने वाली उड़ानों के नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए उड़ानों को स्थानांतरित करने पर नियंत्रण रखना।
- हवाईअड्डे के आपातकालीन कर्मचारियों और अन्य नामित कर्मियों को अलर्ट करते रहना, जब हवाई जहाज को उड़ान में कठिनाई होती है।
- एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर या एटीसी रेडियो का संचालन करता है और हवाईअड्डे के आसपास के क्षेत्र में काम करने वाले विमानों को नियंत्रित करने के लिए रडार की निगरानी करता है।

वायु यातायात नियंत्रकों के कौशल

संचार कौशल - जब पायलट निर्देशों के लिए नियंत्रण टॉवर से संपर्क करते हैं, तो हवाई यातायात नियंत्रकों को उनके अनुरोधों को ध्यान से सुनना चाहिए और स्पष्ट रूप से बोलकर जवाब देना चाहिए।

एकाग्रता कौशल और सतर्कता - वायु यातायात नियंत्रकों के लिए एकाग्रता कौशल और सतर्कता हर समय काम आती है। उन्हें अपने कार्य में एकाग्रता रखनी चाहिए।

निर्णय लेने का कौशल - नियंत्रकों को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। कई बार आपातकालीन स्थिति में उन्हें निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए।

मल्टीटास्किंग स्किल्स - कंट्रोलर को कई फ्लाइट्स की क्रियाओं को समन्वित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें एक साथ कई कामों को करना आना चाहिए।

समस्या-समाधान कौशल - नियंत्रकों को जटिल परिस्थितियों को समझने और महत्वपूर्ण जानकारी की समीक्षा करने और पायलटों को एक उचित समाधान प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

कार्य सारिणी

अधिकांश हवाई यातायात नियंत्रक पूरे समय काम करते हैं, और कुछ को अतिरिक्त घंटे काम करना चाहिए। क्योंकि अधिकांश नियंत्रण टॉवर और मार्ग केंद्र घड़ी के चारों ओर संचालित होते हैं, नियंत्रक दिन, शाम और रात के बीच पारियों को घुमाते हैं। कंट्रोलर सप्ताहांत और छुट्टी की पाली में भी काम करते हैं।

एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर या एटीसी की करियर संभावनाएं

एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर या एटीसी एयरपोर्ट कंट्रोल ऑपरेटर, कंट्रोल टॉवर रेडियो ऑपरेटर, फ्लाइट कंट्रोल टॉवर ऑपरेटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्पेशलिस्ट (एटीसीएस), एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कंट्रोलर (सीपीसी), एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एनरूट ऑप्शन), एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (टॉवर ऑप्शन) आदि रुपों में काम कर सकते हैं।





बतौर मेकअप आर्टिस्ट बनाएं अपना भविष्य

अगर आप भी खुद को और दूसरों को खूबसूरत बनाने में रूचि रखते हैं तो बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपना भविष्य देख सकते हैं।

आज के समय में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, चाहे वह महिला हो या फिर पुरूष। सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग मेकअप पर निर्भर हैं। घर से बाहर शायद ही कोई महिला बिना मेकअप के निकलती है। मेकअप के इस दौर को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है, टेलीविजन, फिल्म और फैशन इंडस्ट्री ने। इनके कारण पहले जहां सिर्फ महिलाएं ही मेकअप करती नजर आती थी, वहीं अब पुरूष भी इनसे पीछे नहीं हैं। इन सभी को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट ही वह व्यक्ति होता है जो किसी भी आर्टिस्ट को उसके किरदार में ढालने में एक अहम भूमिका निभाता है।

मेकअप आर्टिस्ट का कार्य

किसी भी चेहरे को सुंदर बनाना मेकअप आर्टिस्ट का मुख्य कार्य होता है। मेकअप आर्टिस्ट यह पता लगाता है कि किसी के चेहरे के अनुसार उस पर कैसा मेकअप सूट करेगा, वो व्यक्ति कैसे सुंदर लगेगा। ये सारा काम मेकअप आर्टिस्ट का होता है। फिल्मों और टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कि कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की बहुत सुंदर दिखने लगती है। ये सब मेकअप आर्टिस्ट का ही कमाल होता है। लड़कियों की तरह ही लड़कों का भी मेकअप होता है, जिससे वह ज्यादा स्मार्ट दिखें।

किस तरह का करें कोर्स

मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए बुहत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस क्षेत्र में महरत हासिल करने के लिए कोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेकअप किसी व्यक्ति की स्किन से जुड़ा मामला है, आपने कोई प्रॉडक्ट उस व्यक्ति पर लगाया और वो खराब हुआ तो उसकी स्किन हमेशा के लिए खराब हो सकती है। ऐसे में आपको मेकअप आर्टिस्ट से जुड़ा कोर्स जरूर करना चाहिए। जिसमे आप मेकअप और कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट से जुड़ी बारीकियों को समझ सके। इसके लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शामिल हैं। इसमें दाखिला आप 12वीं के बाद ले सकते हैं। इन कोर्स में उम्र की कोई सीमा नहीं होती है।

इन स्किल्स की जरूरत

मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपका क्रिएटिव माइंड होना बेहद आवश्यक है, जिससे आप अपने क्लाइंट की पर्सनैलिटी के अनुरूप मेकअप कर पाएं। हर चेहरा एक जैसा नहीं होता। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति क्लाइंट की डिमांड और मौके के हिसाब से परफेक्ट मेकअप कर पाने में सक्षम होता है, उसे इस क्षेत्र में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही एक मेकअप आर्टिस्ट को हर स्टाइल और गेटअप के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड के बारे में हमेशा रिसर्च करती रहनी चाहिए।

करियर कहां बनाए

आप इस फील्ड में कई जगह करियर बना सकते हैं। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम कर प्रतिमाह लाखों रुपए कमा सकते हैं। बड़े- बड़े एक्टर्स को पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट की तलाश होती है। इसके अलावा आप टीवी चैनल, प्रॉडक्शन हाउस, फैशन इंडस्ट्री में नौकरी की तलाश कर सकते हैं। यहां भी मेकअप आर्टिस्ट की काफी ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप किसी के अधीन नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद भी मेकअप का काम शुरू कर सकते हैं।

कितनी होगी सैलरी

मेकअप आर्टिस्ट की सैलरी आपके कार्य, कार्य स्थल और अनुभव पर निर्भर करता है। अगर आप फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और अन्य स्थानों में कार्य कर रहे हैं तो प्रतिमाह लाखों रूपए कमा सकते हैं, वहीं अपना रोजगार शुरू करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं।

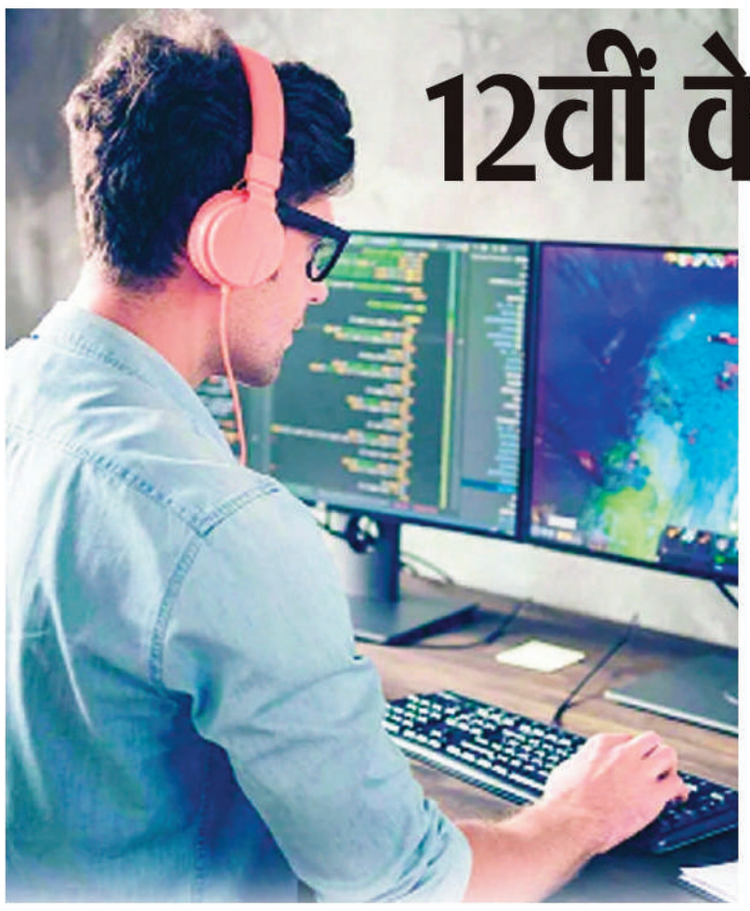

12वीं के बाद करें गेम डिजाइनिंग का कोर्स

अगर आप भी 12वीं के बाद किसी ऐसे कोर्स की तलाश में हैं, जहां पर आपके कॅरियर ग्रोथ के साथ अच्छा पैसा कमा सकें। तो बता दें कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको एक बेहतरीन कॅरियर आप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। बता दें कि इस फील्ड में आने के बाद आपको किस तरह का कॅरियर ग्रोथ मिलेगा। इस फील्ड में आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस आर्टिकल में मिलेंगे। ऐसे में अगर आप भी 12वीं के बाद किसी बेहतरीन फील्ड की तलाश में हैं, तो गेमिंग फील्ड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।

वर्तमान समय की बात करें तो देश में गेमिंग इंडस्ट्री में 50,000 से ज्यादा लोग फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। जिसमें से 30 फीसदी लोग प्रोग्रामर और डेवलपर के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं इस फील्ड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर लाखों की संख्या में जॉब्स पैदा होने की संभावनाएं हैं।

गेम डिजाइनर गेम के कैरेक्टर्स, गेम के लेवल के अलावा तमाम बारीकियों को ध्यान में रखकर उसे इंट्रेस्टिंग बनाने पर फोकस करते हैं। वहीं गेम राइटर डायग्राम आदि बनाकर उसके अलग-अलग वर्जन को तैयार करते हैं। गेम डिजाइनर को टेक्निकल नॉलेज होने के साथ ही सोच में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। गेम तैयार करने के लिए उसकी डिजाइन, डेवलपर्स, आर्टिस्ट्स और अन्य प्रोफेशनल की टीम एक साथ वर्क करती है।

क्वालिफिकेशन

- छात्र ने साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास किया हो।
- कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना जरूरी होता है।
- गेम डिजाइनर बनने के लिए आपकी इंग्लिश भाषा पर अच्छी पकड़ होनी जरूरी है।
- इस फील्ड में आप गेम डिजाइनिंग, गेम डेवलपिंग, आर्ट, एनिमेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशन या मार्केटिंग में बैचलर डिग्री या पेशेवर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं।

जरूरी स्किल्स

- गेमिंग फील्ड में कॅरियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के पास कैरेक्टर डिजाइन, एनिमेशन, कांसेप्ट आर्ट और विजुअल इफेक्ट की जानकारी होनी चाहिए।
- इस फील्ड में 2 डी गेम डेवलपर्स, 3 डी गेम डेवलपर्स और जावा आदि में अपार संभावनाएं हैं।
- इस फील्ड में डिजाइनिंग के साथ 2डी सॉफ्टवेयर और 3डी मॉड्यूलिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
- ऑडियो इंजीनियर के लिए युवाओं के पास साउंड इंजीनियरिंग और अन्य लैंग्वेज की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

जॉब प्रोफाइल

इस फील्ड में युवा एनिमेटर, क्यूएक टेस्टर, ऑडियो इंजीनियर, गेम डिजाइनर, गेम डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोड्यूसर, मैनेजर्स, कास्टर्स, ईस्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स, स्ट्रीमर्स, इंफ्यूएंसर्स के तौर पर अपना कॅरियर बना सकते हैं।